A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 19 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 310, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

यूपी में एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की सियासी होड़!

डॉ. प्रांजल सिंह

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की होड़ मची है। इस बार राजनीतिक मंच की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। विगत 7 मई 2025 को लखनऊ में स्थित सपा मुख्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में 'प्रबुद्ध सभा' का आयोजन किया गया। इस सभा में अखिलेश यादव ने अपने साथ हरी शंकर तिवारी के पुत्र कुशल तिवारी को मंच पर बैठाया। इस आयोजन का संचालन कर रहे पवन पांडेय योगी सरकार में मारे गए ब्राह्मणों की सूची पढ़ते हुए 'मठाधीश ने ठाना है, ब्राह्मणों को यूपी से मिटाना है, ब्राह्मणों ने भी अब माना है, 27 में पीडीए के सत्ताधीश की सरकार को लाना है। जैसे नारों से पूरा सभागार गूंज रहा था।'

'जय परशुराम' के उद्घोष से यह प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठने के लिए संकल्पित भी हो रही थी। यह प्रयास राजनीतिक रूप से तब गर्म हो गया जब पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर जिले के दिवंगत नेता हरिशंकर तिवारी के घर ईडी ने छापा मारा, हरिशंकर तिवारी जिन्हें राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों के बड़े चेहरे के रूप में माना जाता था। वे अपने दोनों बेटे भीम शंकर तिवारी उर्फ़ कुशल तिवारी और उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी के साथ 2021 में सपा में शामिल हो गये थे।

ब्राह्मण परिवारों के सपा में शामिल होने से पार्टी की बागड़ोर संभाल रहे अखिलेश यादव ने बयान दिया कि इतना बड़ा परिवार अब हमारे साथ जुड़ गया है तो फिर सपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सपा में आकर आपने परिवार की लड़ाई को और मज़बूत कर दिया है। अखिलेश यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में 'ब्राह्मण वर्चस्व' को स्वीकार करने वाला मालूम होता है। हालांकि पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मण 10-12 प्रतिशत ही हैं। राजनीतिक तौर पर यह संख्या एक निर्णायक भूमिका भी अदा करती है। जिनके समर्थन की लालसा प्रत्येक राजनीतिक दल को होती है। यही कारण है कि भाजपा दिनेश शर्मा को सूबे का उपमुख्यमंत्री बना कर ब्राह्मण वर्चस्व को ही संतुलित करना चाहती है।

वहीं बसपा 2021 के अगस्त और सितंबर से 'प्रबुद्ध वर्ग सम्मलेन' के ज़रिए अपने साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। जिसमें सतीशचन्द्र मिश्र, मथुरा के पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा, नकुल दुबे को आगे रख रही है जो ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ते रहे हैं। हालांकि बसपा का यह दावा कितना कारगर होगा, उसका एक आकलन 2014 के चुनाव से ठीक पहले उसकी राजनीतिक योजनाओं में देखा जा सकता है। जहां मायावती को यह उम्मीद थी कि वे जाटव और अन्य उपजातियों को टिकट देकर दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों को संतुष्ट कर पाएगी। बसपा के इस प्रयास ने उसके अपने ही कार्यकर्ताओं (विशेष तौर पर दलित कार्यकर्ता) को भ्रमित कर दिया। खामियाज़ा यह हुआ कि पार्टी उन जगहों से भी चुनाव हार गई जहां से पार्टी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी।

रही बात अखिलेश यादव के ब्राह्मणों के प्रति राजनीतिक लाभ का जिसका आकलन बहुत सूक्ष्मता से करने की जरूरत है। क्योंकि अखिलेश यादव द्वारा पीडीए बना कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय का एक सफल संदेश दिया जा चुका है। जिसका लाभ उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ज़मीन उसी की मज़बूत हो सकती है जो 2014 से लेकर 2022 के चुनावों में बिखरी हुई पिछड़ी और वंचित जातियों को एक साथ लामबंद करने में कामयाब हो जाता है। सपा ने अपने पीडीए फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में 56 प्रतिशत दलित और 34 प्रतिशत गैर यादव के वोट अपने पाले में खींच पाई।

डॉ. आंबेडकर ने जनवादी क्रांति का नया सूत्रीकरण किया था। इस सूत्रीकरण में बाबा साहेब ने दलित, पिछड़ों के नेतृत्व में एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ बनाने की योजना पेश की थी जिसमें पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मिलाकर मोर्चा बनाया जाए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए पीडीए के द्वारा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व की और मोड़ दिया था। जिसमें आवश्यकता यह थी कि जो पिछड़ी जातियां जिनमें कुर्मी, कोइरी, पासी, निषाद जो एक समय में समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन ब्राह्मणों के साथ सपा का किया गया यह गठबंधन पूरे पीडीए गठजोड़ को ही संदिग्ध कर देता है।

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जातियों मंव कोई समरूपता नहीं हैं। इन्हें तीन वर्गों में बांट कर देखा जा सकता हैं। एक वर्ग उन समूहों का है; जो सूबे की शुरूआती राजनीति से ही सशक्त और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर रहें है। जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश की राजनीति में शुरूआती दौर में किया करती थी। जिनमें कमलापति त्रिपाठी वर्तमान में राजेश मिश्र, प्रमोद तिवारी मुख्य रूप से शामिल हैं।

दूसरा वर्ग उन समूहों का है जो केवल राजनीतिक दलों से संरक्षण चाहते हैं। जिससे वह अपना व्यापार, ठेकेदारी, और एक संस्थागत वर्चस्व को बनाए रखें। बसपा ने सबसे पहले इन्हीं वर्गों को अपने राजनीतिक उदेश्यों से जोड़ा था। तीसरा वर्ग, उन समूहों का है जो आज भी किसानी कर के जीवन व्यापन कर रहें है, या फिर गांवों में जजमानी प्रथा को कायम रखते हुए अपने घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब पंडितों का यह समूह राजनीतिक रूप से सशक्त होने से ज़्यादा अपनी सामाजिक और आर्थिक हालत को सुधारे की कोशिश कर रहा है। सपा के साथ जाने पर किन वर्गों को फ़ायदा होगा यह भी आकलन करने की आवश्यकता है।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय पर चलने वाले जिस राजनीतिक दल ने ऊंची जातियों के साथ गठबंधन कर अपने राजनीतिक लक्ष्य को समाने रखा है, वह अपने मूल राजनीतिक आधार को खोता हुआ ही नज़र आया है। बसपा इसका एक बड़ा उदाहरण है। पार्टी आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

समाजवादी पार्टी को यह गठबंधन कितना फ़ायदा और कितना नुकसान देगा इसका आकलन अभी बाक़ी है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किए गए इस तरह के फैसले पार्टी के हित में बहुत कम रहे हैं और उसका नुकसान पार्टी को लंबे समय तक चुकाना पड़ा है। सपा का ब्राह्मणों के साथ गठबंधन भाजपा के राजनीतिक दबदबे को रणनीतिक चुनौती देता है। अगर गठजोड़ संतुलन और संवाद के बजाय तुष्टिकरण का रूप ले लेता है तो पार्टी को पारंपरिक आधार खोने, संदेश की अस्पष्टता और गठबंधन की राजनीति में विरोधाभास जैसी समस्याओं का समाना करना पड़ सकता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

धीरे-धीरे
बहुत पुराना
बरगद सूख रहा है।

जड़ में दीमक
और तने पर
हैं, प्रगति के घाव।
साथ छोड़ते
पीले पत्ते
क्षत-विक्षत है छॉव।
नए दौर का
मौसम अंधा,
बहरा, मूक रहा है।
टहनी-टहनी
उछल-उछल कर
चिड़िया हार गई।
तिनका-तिनका
नीड हुआ
मेहनत बेकार गई।
नई हवा में
उसका सारा
साहस चूक रहा है।
धीरे-धीरे
बहुत पुराना
बरगद सूख रहा है।

– रघुवीर शर्मा

पुणे की तरह पटना, मुंबई जैसा होगा अब मोतिहारी

● पीएम बोले-जैसे रोजगार गुरुग्राम में वैसे गयाजी में मिलेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा-पहली प्राइवेट नौकरी पर 15 हजार देंगे

मोतिहारी (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में हैं वैसे ही अवसर गयाजी में बने। पुणे की तरह पटना होगा। अपने 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। साथ ही आरजेडी-कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम बोले- अब बिहार में विकास करने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे। यानी नीतिश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने बिहार से बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी खत्म कर दी। मोतिहारी ने पीएम मोदी ने घोषणा की कि आने वाले समय में पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15 हजार रुपए देने जा रही है।

नॉर्वे की जितनी आबादी बिहार में उतने घर दिए

गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए। इनमें से करीब 7 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में कुछ देशों की जितनी आबादी है, बिहार में उतने गरीबों को हमने पक्के घर दिए हैं। अकेले मोतिहारी जिले में हमने 3 लाख के करीब गरीब परिवारों को घर दिए हैं। ये गिनती लगातार बढ़ रही है। मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई। उन्होंने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं।

हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार हर युवा को रोजगार

नीतिश सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। 10 लाख को रोजगार दिया जा रहा है। नीतिश जी की सरकार का युवाओं पर फोकस है। ये लोग रोजगार के नाम पर आपकी जमीनें लिखवा लिया करते थे। अब ऐसा नहीं है सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। एनडीए की सरकार के साथ मिलकर बिहार ने ये सफर तय किया है। बिहार की इस धरती से मैंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। बिहार के पास ना सामर्थ्य की कमी है और ना ही संसाधन की। इससे पहले पीएम खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश होती रही। मोदी-मोदी और भारत माता के नारे लगते रहे।

छग शराब घोटाले में भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार

● पूर्व सीएम बोले-जन्मदिन के तोहफे के लिए मोदी-शाह का धन्यवाद

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से चैतन्य की 5 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल कोर्ट से अभी आदेश नहीं आया है। कोर्ट में भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इसके पहले भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडाणी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था।

स्पेन यात्रा का तीसरा दिन

मर्काबार्ना का समग्र मॉडल मप्र के लिये प्रेरणादायक : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। सीएम का स्पेन यात्रा का तीसरा दिन था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बार्सिलोना स्थित मर्काबार्ना का समग्र मॉडल मध्यप्रदेश के लिए उपयोगी हो सकता है। मध्यप्रदेश में बढ़ते कृषि उत्पादन को देखते हुए बेहतर 'पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट' और निर्यात प्रणाली की आवश्यकता है। स्पेन प्रवास के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मर्काबार्ना के भ्रमण के दौरान यह बात कही। यह संस्थान 250 एकड़ में फैला हुआ यूरोप का प्रमुख फूड लॉजिस्टिक्स हब है, जहाँ उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग और वितरण की व्यवस्थाएं एकीकृत रूप से संचालित होती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज मध्यप्रदेश को सिर्फ उत्पादन की नहीं, बल्कि कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, भंडारण, और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच की भी चुनौती है। इस दिशा में मर्काबार्ना का अनुभव एक मॉडल के रूप में सामने आता है, जिससे प्रेरणा लेकर प्रदेश के खाद्य उत्पादकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। मर्काबार्ना के सीईओ ने मध्यप्रदेश के प्रति रूचि जताई। मर्काबार्ना के सीईओ पाब्लो विल्लानोवा ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिवादन करते हुए कहा कि भारत और स्पेन के बीच कृषि लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग की संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रति विशेष रुचि और भविष्य में द्विपक्षीय ज्ञान साझेदारी पर सहमति जताई।

फार्म-टू-फोर्क जैसे मॉडल होंगे लागू- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'फार्म-टू-फोर्क' मॉडल, कोल्ड चेन प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, ट्रेसेबिलिटी और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मर्काबार्ना द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में विकसित किए जा रहे मेगा फूड पार्क, एग्रीबिजनेस क्लस्टर और ग्रामीण उद्योग केंद्रों में इन नवाचारों को समाहित किया जाएगा।

खाद्य अपशिष्ट नियंत्रण और नवाचार के क्षेत्र में भी प्रेरणा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मर्काबार्ना में संचालित फूड बैंक, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली और फूड-टेक स्टार्टअप्स के लिए तैयार किए गए इनक्यूबेशन मॉडल का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्थाएं मध्यप्रदेश में नवाचार-आधारित कृषि नीति को मजबूती देंगी।

निर्यात और वैश्विक पहुंच के लिए ठोस रणनीति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में गेहूं, चावल, फल, सब्जियों और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। मर्काबार्ना जैसे केंद्रों से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश में पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।

निवेश और साझेदारी के लिए खुला निमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मर्काबार्ना प्रबंधन को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वसुधैव कुटुंबकम' के मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्यप्रदेश वैश्विक साझेदारियों के लिए तैयार है। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और तकनीकी निवेश को बढ़ावा भी दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह यात्रा कृषि आधारित विकास के एक नए चरण की भूमिका तय कर रही है। अब मध्यप्रदेश केवल उत्पादन आधारित राज्य नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत भागीदार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

बेहाल पाकिस्तान को अब आईएमएफ ने दिया झटका

बांध बनाने के सपने पर लगा ग्रहण, सूखा मरेगा शहबाज का देश

इस्लामाबाद (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, जिससे इस्लामाबाद की देश में बड़े बांध बनाने की योजना खटाई में पड़ सकती है। पाकिस्तान ने बड़े बांध बनाने के लिए वस्तुओं पर 1 प्रतिशत जल संग्रहण उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आईएमएफ ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसके बदले में संघीय विकास कार्यक्रम के किसी भी बड़े आकार के वित्तपोषण के लिए 18 फीसदी मानक बिक्री कर की दर बढ़ाने का सुझाव दिया है। आईएमएफ ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब पाकिस्तान को अपने दो बांध के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है। दैनिक ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को डायमर-भाषा बांध की लागत में संशोधन और चिनाब नदी पर एक नया बांध बनाने के लिए धन की जरूरत है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसके लिए कम से कम 800 अरब रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएमएफ ने जल संग्रहण उपकर (वॉटर स्टोरेज सेस) लगाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। सरकार इसे देश में बनने वाले हर उत्पाद पर लगाना चाहती थी। पाकिस्तान की सरकार ने इस सेस को दो बड़े बांधों के वित्तपोषण और भारत की वॉटर स्ट्राइक से निपटने के लिए एक नए बांध निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है। सेस लगाने से पाकिस्तान सरकार को फायदा होता क्योंकि इसका 100 फीसदी हिस्सा संघीय खजाने में रहता। वहीं, आईएमएफ से प्रस्तावित बिक्री कर संघीय विभाजन पूल का हिस्सा बन जाएगा और राज्यों को भी पहुंचेगा।

सिंधु जल संधि पर रोक से घबराया पाकिस्तान

भारत के सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान घबराया है और बांधों के निर्माण में तेजी चाहता है लेकिन तीन बांधों की संशोधित लागत का आकलन करने से पता चलता है कि चिनाब और डायमर-भाषा बांध के लिए अतिरिक्त 800 अरब रुपये की आवश्यकता है। शेष वित्तीय आवश्यकताओं को जोड़ने के बाद केवल तीन बांधों के लिए 1.35 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की आवश्यकता है। इसमें मोहमंद बांध भी शामिल है। इस बीच जल संसाधन मंत्रालय ने सरकार को सूचित किया है कि बजट आवंटन की मौजूदा गति से मोहमंद बांध को पूरा करने में 15 साल और दियामर-भाषा बांध का काम पूरा होने में 20 साल से ज़्यादा लगेंगे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35°c न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 19 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

मीडिया ट्रायल हुआ सीजेआई पर ऐक्शन की पॉवर नहीं

- जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा-इससे मेरी छवि खराब हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार की ओर से महाभियोग की तैयारी के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 14 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास पर बड़े पैमाने पर कैश पाए जाने की खबर मिली थी। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने दोषी पाया था। उस रिपोर्ट के बाद उनका इलाहाबाद ट्रांसफर

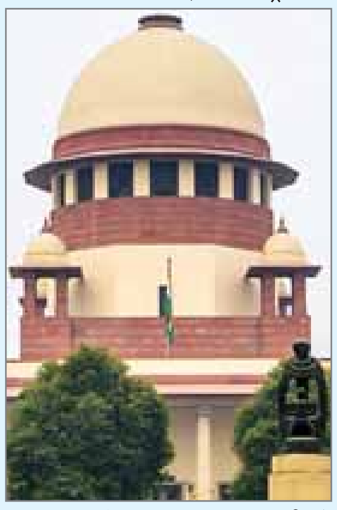

किया गया और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई थी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही महाभियोग चलाने की तैयारी है, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ 6 अहम दलीलें दी हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सबसे बड़ा आरोप मीडिया ट्रायल का लगाया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक किया गया और इसके चलते मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे मेरी छवि खराब हुई है और मेरे करियर पर भी असर पड़ा है। जस्टिस वर्मा ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से तय नियमों का भी इस तरह जानकारी सार्वजनिक करके उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कमेटी की फाइनल रिपोर्ट छपी है और इस तरह गोपनीयत का उल्लंघन किया गया। जस्टिस वर्मा ने एक तर्क न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित दिया है।

छांगुर गैंग के 18 बैंक खातों में 68 करोड़ का लेन-देन

- *विदेश से भी 7 करोड़ की फंडिंग, ईडी रेड में मिला खजाना*

बलरामपुर (एजेंसी)। अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा यूपी एटीएस के बाद अब ईडी के निशाने पर आ गया है। एक दिन पहले गुरुवार सुबह-सुबह ईडी की कई टीमों ने यूपी से लेकर मुंबई तक छांगुर बाबा के ठिकानों पर छापा मारा। यूपी के 12 ठिकानों और मुंबई के बांद्रा और माहिम में अफसरों ने रेड किया। अब तक जांच में छांगुर गैं के 30 में से 18 बैंक खातों में लगभग 68 करोड़ रुपये का लेन-देन सामने आया है। पिछले तीन महीनों में विदेश से करीब 7 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई है। इन फंडिंग का इस्तेमाल छांगुर गिरोह ने प्रॉपर्टी खरीदने और अवैध धर्मांतरण के लिए किया। ईडी छांगुर बाबा की संपत्तियों, आयकर रिटर्न और जमीन से जुड़े

दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पैसा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में पहुंचा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में सक्रिय हैं। ये एजेंसियां छांगुर बाबा के वित्तीय नेटवर्क को खंगाल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने अपने नेटवर्क को संचालित करने के लिए कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे 'प्रोजेक्ट' का मतलब लड़कियां, 'मिट्टी पलटना' का मतलब धर्म परिवर्तन और 'काजल लगाना' का मतलब मनोवैज्ञानिक हेरफेर। ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती हैं। बाबा की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। उसके विदेशी फंडिंग नेटवर्क के स्रोतों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है। मुंबई में ईडी ने जिस शहजाद शेख से घंटों पूछताछ की, वह नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन का सहयोगी है। नीतू और नवीन छांगुर बाबा के राजदार हैं। ईडी ने शहजाद द्वारा बेची गई जमीन और अन्य लेन-देन की जानकारी भी जुटा ली है।

विकास के साथ कला और संस्कृति का समानांतर उत्थान आवश्यक : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

शान-ए-विन्ध्य सम्मान समारोह में हुए शामिल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक अधोसंरचना के साथ-साथ कला और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रीवा स्थित राजकपूर ऑडिटोरियम जैसे मंचों पर स्थानीय एवं राष्ट्रीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिलना एक सकारात्मक पहल है, जिससे समाज में ऊर्जा और जीवंतता का संचार होता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल शान-ए-विन्ध्य सम्मान समारोह में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि हंसाने वाले लोग समाज में विरले होते हैं। श्री एहसान कुरैशी जी ने अपनी कला से लोगों को गुदगुदाया, यह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों से न केवल कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि युवाओं में भी रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उन्होंने समारोह के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि शान-ए-विन्ध्य जैसे आयोजन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ ही क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी समृद्ध करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों एवं कलाकारों को सम्मानित भी किया।

समारोह में देश के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री एहसान कुरैशी सहित अन्य कलाकारों ने अपनी हास्य प्रस्तुतियों से उपस्थितजन को आनंदित किया। सांसद श्री जनार्दन मिश्र, नगर निगम अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त डॉ. श्री सौरभ सोनवड़े सहित बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।

भाषा ज्ञान के मार्ग में बाधक नहीं बने इस सोच का सफल क्रियान्वयन है 'हिंदी में एमबीबीएस'

15 से 20 प्रतिशत छात्रों ने मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं में हिंदी का किया उपयोग

भोपाल। भाषा ज्ञान के मार्ग में बाधक नहीं बने इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत है। हिंदी भाषा में एमबीबीएस की व्यवस्था इसी सोच का सफल क्रियान्वयन है। भाषा को अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का माध्यम बनाकर छात्रों को सशक्त करना सरकार का लक्ष्य है। यह पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। मध्यप्रदेश सरकार की मातृभाषा हिंदी में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प अब नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन की ठोस रूपरेखा के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा हिंदी को सशक्त बनाने सतत नवाचार किए जा रहे हैं।

15 से 20 प्रतिशत छात्रों ने मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं में हिंदी का किया उपयोग- कुल सचिव मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने बताया कि वर्ष 2022 में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया गया था और इन्हें शैक्षणिक सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह नवाचार अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, जिसमें केवल प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 से 20 प्रतिशत छात्रों ने मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं में हिंदी भाषा का उपयोग किया है। यह प्रथम बैच वर्ष 2027-28 में स्नातक होकर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्रों से प्रश्नपत्र दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर दे सकें। साथ ही हिंदी भाषा के उपयोग की सटीक जानकारी के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं।

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा संकाय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को मातृभाषा में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा और प्रायोगिक शिक्षण में मातृभाषा में परीक्षा देने वाले छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो साथ ही परीक्षकों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि वे मातृभाषा को समझते हों और उसी में छात्रों से संवाद कर सकें। मातृभाषा में परीक्षा देने वाले छात्रों को संस्थागत स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए विशेष समस्या निवारण कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही, इन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमन्त खण्डेलवाल आज जबलपुर प्रवास पर

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल 19 जुलाई, शनिवार को जबलपुर जिले के प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल दोपहर 2.10 बजे जबलपुर के अंधमुख बधिर बायपास चौराहा से प्रारंभ होने वाली रैली में शामिल होंगे। सायं 4 बजे मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप रात्रि 8.30 बजे पूर्व सांसद श्रीमती जयश्री बेनर्जी, रात्रि 9 बजे पूर्व सांसद श्री रविनंदन सिंह एवं रात्रि 9.30 बजे प्रदेश शासन के मंत्री श्री राकेश सिंह के निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट करेंगे।

शहडोल जिले में सीवर लाइन कार्य के दौरान हुई दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने व्यक्त किया शोक

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शहडोल जिले में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो श्रमिकों श्री मुकेश बैगा एवं श्री महिपाल बैगा के दबने से हुए निधन पर गहन दुःख व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को यह वज्र समान पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को शीघ्र सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

जमीन के बदले नौकरी

लालू यादव को 'सुप्रीम झटका'

- ट्रायल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने लालू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई तेज करने का निर्देश भी जारी किया। हालांकि, लालू के लिए राहत वाली बात यह रही कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से उन्हें छूट मिल गई। 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि

कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। एचसी ने लालू यादव की सीबीआई एफआईआर रद्द करने की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के वेस्ट-सेंट्रल जोन में ग्रुप डी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कहा गया कि नौकरियां लालू के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन रजिस्टर करने के बदले में की गई थीं। लालू यादव ने अपनी याचिका में एफआईआर, 2022, 2023 व 2024 में दाखिल तीन आरोपपत्रों को रद्द करने और उसके बाद के संज्ञान आदेशों को खारिज करने की मांग की थी। यह मामला 18 मई, 2022 को यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

संसद सत्र

इंडिया अलायंस की मीटिंग आज दूर रहेंगे एएपी और टीएमसी

- उद्धव भी बढ़ा सकते हैं चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले इंडिया अलायंस के दलों की शनिवार को मीटिंग है। संसद सत्र में एकता के साथ मुद्दे उठाने की पहल के लिए यह मीटिंग आयोजित हो रही है, लेकिन इसमें ही झटका लगता दिख रहा है। इसकी वजह है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने दूरी बना ली है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर भी संशय है। आप का साफ तौर पर कहना है कि वह अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है।.एएपी के राज्यसभा सांसद संजय

सिंह ने कहा, हम अब इंडिया ब्लॉक में नहीं हैं। वह पहले भी कह चुके हैं कि पिछले साल लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने अपना मकसद पूरा कर लिया था।

रॉबर्ट वाड्रा के लिए पहली बार खुलकर बोले राहुल गांधी

- कांग्रेस नेता बोले, 10 साल से मेरे जीजा को कर रहे परेशान

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर पहली बार बोला है। उनके खिलाफ दाखिल की गई नई चार्जशीट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों से रॉबर्ट वाड्रा को सरकार द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में कहा,मेरे बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को इस सरकार ने पिछले दस वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया है। अब जो नई चार्जशीट दायर की गई है, वह उसी राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना की अगली कड़ी है।

पन्द्रह हजार फिट ऊंचाई से 'आकाश' ने किया तगड़ा वार

- स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल टेस्ट

मार गिराए 2 ड्रोन, दागो और भूल जाओ मोड पर करता है काम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम 'आकाश प्राइम' का सफल परीक्षण किया। सेना ने इसका वीडियो गुरुवार को जारी किया। इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को के लिए बनाया गया है। सिस्टम के हरेक लॉन्चर में तीन मिसाइलें हैं, जो 'दागो और भूल जाओ' मोड में काम करती हैं। ये मिसाइलें लगभग 20 फीट लंबी और 710 किग्रा वजनी हैं। प्रत्येक मिसाइल 60 किलोग्राम का

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में यह 15,000 फीट (4500 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे दो ड्रोन मार गिराए। आकाश प्राइम, आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने वारहेड ले जा सकती है। इसके साथ ही यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमैटिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरी आकाश मिसाइल प्रणाली के विकास में लगभग 1,000 करोड़ रुपए (17 करोड़ डॉलर) की लागत आई है। यह अन्य देशों में विकसित ऐसी ही प्रणालियों के मुकाबले 8-10 गुना कम है।

- **डीआरडीओ ने डेवलप किया आकाश न्यू जेनरेशन हथियार सिस्टम-** भारतीय वायुसेना ने पहले ही 10,900 करोड़ रुपये में आकाश के 15 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया है। अखबार ने पहले ही इसकी जानकारी दी थी। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जेनरेशन हथियार सिस्टम भी विकसित किया है। इसकी शुरुआती मारक क्षमता 30 किलोमीटर है, जिसे बाद में और बढ़ाया जाएगा। आकाश-एनजी का पहला परीक्षण जनवरी 2021 में किया गया था। इसमें छोटे आकार की मिसाइलें, आधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लांचर, मल्टी-फंक्शन रडार और कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम हैं।

अनादि ने इमर्जिंग विमेन्स टूर्नामेंट में 10 विकेट लेकर रचा इतिहास

इंदौर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित एमर्जिंग विमेन्स मल्टी-फॉर्मेट टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश की तेज गेंदबाज अनादि तागड़े ने अपनी प्रतिभा का अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

लाल गेंद के चार दिवसीय मुकाबले में टीम सी की ओर से खेलते हुए अनादि ने लिए 10 विकेट

अपने नाम किए – पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में भी 5 विकेट, यह उपलब्धि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए स्वप्न से कम नहीं। उनकी गेंदबाज़ी में न केवल रफ़्तार थी, बल्कि धार, अनुशासन और अनुभव की झलक भी थी, जिससे वरिष्ठ और भारत की अनुभवी खिलाड़ी भी चकित रह गईं।

गेंद से शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही अनादि ने बल्लेबाज़ी में भी कमाल किया – दूसरी पारी में सर्वाधिक 32 रन बनाकर टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। यह पारी उनके जुझारूपन और ऑलराउंडर क्षमता का प्रमाण है।

टीम सी में मध्यप्रदेश की दमदार मौजूदगी

अनादि तागड़े के साथ-साथ मध्यप्रदेश की चार अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेल रही हैं। आयुषी शुक्ला, सौम्या तिवारी, वैष्णवी शर्मा और संस्कृति गुप्ता – ये सभी टीम ष्ट का हिस्सा हैं। यह पांचों खिलाड़ी प्रदेश में महिला क्रिकेट के उभार और प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था का परिचायक हैं।

अनादि की उपलब्धियां

मात्र 16 वर्ष की आयु में अनादि ने पहले ही अनेक उपलब्धियाँ अर्जित कर ली हैं-

- भारत क्तटीम की ओर से दक्षिण अफ्रीका 19 के विरुद्ध त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रतिनिधित्व
- वरिष्ठ महिला एकदिवसीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन
- 19 राष्ट्रीय टी20 प्रतियोगिता में 6 विकेट और हैट्रिक *23 वनडे टूर्नामेंट एवं सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी में चयन
- इस वर्ष देहरादून में आयोजित मल्टी डे टूर्नामेंट में चयन
- एमपी विमेन्स प्रीमियर लीग में चंबल घड़ियाल की और से खेलते हुए 'हाईएस्ट डॉट बॉल अवॉर्ड' विजेता उनकी गेंदबाजी में धार और बल्लेबाज़ी में संतुलन उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर रहा है। चार दिवसीय मुकाबलों के बाद अब टूर्नामेंट का रुख 21 जुलाई से एकदिवसीय प्रारूप और फिर टी-20 की ओर होगा। यह मल्टी-फॉर्मेट ढांचा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के दबाव, रणनीति और कौशल की तैयारी का सशक्त मंच प्रदान कर रहा है।

वर्किंग प्लान लेकर नहीं पहुंचे पीडब्ल्यूडी अफसर, सांसद की फटकार

भोपाल में स्कूलों में प्रतिबंधित होंगे ई-रिक्शा, एक सप्ताह में लेफ्ट टर्न सुधारने को कहा

भोपाल (नप्र)। भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को फिर से जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम समेत अन्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें वर्किंग प्लान लेकर नहीं आने पर सांसद ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को फटकार लगाई। बैठक में फैसला हुआ कि स्कूलों में ई-रिक्शा प्रतिबंधित किए जाएंगे। एक सप्ताह में लेफ्ट टर्न सुधारे जाएंगे।

पीडब्ल्यूडी अफसरों के प्लान नहीं लाने पर सांसद ने कहा कि अधिकारी जब भी बैठक में आएं, तैयारी के साथ आएं। अफसर एक सप्ताह में लेफ्ट टर्न व्यवस्था सुधारने का प्लान एस्टीमेट के साथ तैयार करके दें। शहर के 42 चौराहे हैं, जिनमें लेफ्ट टर्न की समस्या है।

इनमें 29 चौराहे पीडब्ल्यूडी और 13 नगर निगम के हैं। दोनों विभाग के अधिकारी मैनिट के ट्रैफिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर इन सभी चौराहों की रिपोर्ट एस्टीमेट के साथ प्रस्तुत करेंगे। लेफ्ट टर्न सुधारने के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

कलेक्टर बोले- ई रिक्शा में भेजना ठीक नहीं

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ई-रिक्शा को स्कूलों में प्रतिबंधित करने को कहा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ई-रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेजना ठीक नहीं है। अतिक्रमण और सड़कों से कंडम वाहन हटाने की मुहिम की भी समीक्षा की गई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बारिश की वजह से दो-तीन दिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, लेकिन बाद में लगातार यह मुहिम जारी है।

सांसद बोले- ट्रांसफॉर्मर और खंबों को भी हटाएं

सांसद शर्मा ने सड़कों पर बेतरतीब तरीके से लगाए गए विद्युत ट्रांसफॉर्मर और खंबों को हटाने कलेक्टर से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में इसके लिए नई पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई थी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग की कमेटी बन चुकी है। इसकी एक बैठक भी हो चुकी है। अगली बैठक में विद्युत विभाग की एमडी और सक्षम अधिकारियों को भी बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया।

सांसद शर्मा ने कहा, पॉलिसी ऐसी बने कि भविष्य में यदि किसी को भी अपने घर के सामने रोड पर या कॉलोनी में विद्युत खंबे लगाना है, ट्रांसफॉर्मर लगाना है तो उसके लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की अनुमतियां लेना आवश्यक किया जाए। जिससे बिजली के खंबे और ट्रांसफॉर्मर शहर की यातायात व्यवस्था में बाधक न बने।

पार्किंग व्यवस्था पर भी हुई बात

पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई। सांसद ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्मार्ट पार्किंग आम नागरिकों के लिए है, न कि स्थायी मासिक पास धारकों के लिए। उन्होंने कहा, पार्किंग स्थल सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक खुलने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मासिक पास की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए। ताकि आमजन के लिए पार्किंग अधिक सुलभ हो सके।

राज्यपाल ने राजभवन में रोपा तुलसी का पौधा

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को राजभवन उद्यान में तुलसी का पौधा लगाया। उन्होंने गमले में तुलसी के बीज बोकर पर्यावरण-संरक्षण का संदेश भी दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 23 जुलाई को समीक्षा बैठक

भोपाल (नप्र)। सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025 एवं राह-वीर योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक 23 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। बैठक में परिवहन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा

परिचित ने किया युवती से रेप

शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण, इनकार पर युवती ने कराया केस दर्ज

भोपाल (नप्र)। भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय युवती के साथ लंबे समय तक रेप का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक शुभम भारती को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि युवक ने शादी का झांसा देकर करीब 3 साल तक युवती का शारीरिक शोषण किया। जब युवती ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने इनकार कर दिया और संपर्क तोड़ लिया।

पुलिस के अनुसार, युवती 6 साल पहले निशातपुरा इलाके में अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात शुभम भारती से हुई, जो उसके ही गांव का रहने वाला है। परिचय बढ़ने पर दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्रेम संबंध बन गए।

युवती ने बताया कि करीब तीन साल पहले शुभम ने मौका पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। जब उसने इसका विरोध किया और परिजनों या पुलिस को बताने की बात कही, तो युवक ने शादी का वादा कर उसे चुप करा दिया।

शुभम ने युवती को जल्द शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। युवती के अनुसार, बीते 3 वर्षों में वह लगातार उसका शोषण करता रहा। कुछ समय पहले जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शुभम ने न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की और संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। शादी से इनकार और मारपीट के बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज करते हुए आरोपी शुभम भारती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इस समय एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। मामले की जांच जारी है।

उरई में भी रुकेगी इंदौर-वाराणसी महाकाल एक्सप्रेस

आज से शुरू होगा प्रायोगिक ठहराव, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया निर्णय

भोपाल (नप्र)। इंदौर से वाराणसी के बीच चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस अब उरई रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए इस ठहराव को मंजूरी दी है। यह ठहराव फिलहाल प्रायोगिक तौर पर दिया गया है, जो 18 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि गाड़ी संख्या 20414 इंदौर-वाराणसी महाकाल एक्सप्रेस 18 जुलाई से उरई स्टेशन पर शाम 7:18 बजे पहुंचेगी और 7:20 बजे रवाना होगी। वहीं, गाड़ी संख्या 20413 वाराणसी-इंदौर महाकाल एक्सप्रेस 22 जुलाई से उरई स्टेशन पर रात 10:17 बजे आएगी और 10:19 बजे रवाना होगी।

ठहराव सफल रहने पर स्थायी व्यवस्था होगी- महाकाल एक्सप्रेस भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर और बीना जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। अब उरई को भी इस महत्वपूर्ण ट्रेन से जोड़ दिया गया है, जिससे यहां के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का भरपूर लाभ लें और रेल यात्रा को सुरक्षित, समयबद्ध व सुविधाजनक बनाएं।

भोपाल में पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा

6 की जगह 10 रुपए लगेंगे, कांग्रेस का विरोध, कहा- इससे तो खाना सस्ता है

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा। मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दूसरी ओर, टॉयलेट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं।

पिछले दिनों एमआईसी की बैठक हुई थी। इसमें सुलभ इंटरनेशनल ने 25 स्थानों पर संचालित सार्वजनिक शौचालय में उपयोगकर्ता शुल्क दर 6 से बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने की मंजूरी चाही थी। एमआईसी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस विरोध कर रही है। शुक्रवार को शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।

एमआईसी मेंबर बोले- सालों से 6 रुपए ही ले रहे थे- इस मामले में एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने बताया कि कई साल से 6 रुपए ही शुल्क लिया जा रहा था। कई बार खुल्ले पैसे को लेकर दिक्कतें होती थीं। लोग खुल्ले लेकर नहीं आते थे। यह बोझ बढ़ाने वाला नहीं है और न ही विरोध जैसी बात है। एमआईसी में यह प्रस्ताव पास हो गया है।

स्वच्छता अभियान पर असर पड़ेगा- पार्षद चौहान ने कहा कि शुल्क बढ़ने से स्वच्छता अभियान पर भी असर पड़ेगा। अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल दूसरे नंबर पर आया है।

भोपाल प्रेस क्लब ने पत्रकारों का जन्मदिन मनाया

भोपाल। भोपाल प्रेस क्लब ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार अरूण पटेल व अजय बोकिल का जन्म दिन इंडियन कॉफी हाउस में मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना, नासिर हुसैन, आरएसएस के प्रवेश विजयवर्गीय, भोपाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय सक्सेना, सचिव विजय शर्मा, ब्रजेन्द्र तिवारी, जगत बहादुरसिंह, गोपाल जैन आदि मौजूद थे।

166 स्थाई और 25 चलित रसोई केंद्रों से जरूरतमंदों को 5 रूपये में भोजन

6 धार्मिक नगरों में श्रृद्धालुओं को भी 5 रूपए में भोजन

भोपाल (नप्र)। दीनदयाल रसोई योजना में नगरीय निकायों द्वारा अब तक करीब 4 करोड़ 60 लाख भोजन थाली का वितरण मात्र 5 रूपये प्रति थाली की दर पर जरूरतमंदों को किया गया है। यह योजना 51 जिला मुख्यालयों के 191 रसोई केन्द्रों के माध्यम से संचालित है। इनमें 166 स्थाई और 25 चलित रसोई केन्द्र कार्यरत हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय और श्रम कार्यों के सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद परिवारों का निरंतर आगमन होता है। नगरीय निकायों द्वारा इनके ठहरने और किफायती दर पर भोजन व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे हैं।

नगरीय निकायों द्वारा संचालन- वर्तमान में 166 स्थाई रसोई केन्द्र में से 16 नगर निगमों में 58 रसोई केन्द्र और 99 नगर पालिका परिषद में 99 रसोई केन्द्र और 9 नगर परिषदों में 9 रसोई केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही 25 चलित रसोई केन्द्र में से 16 नगर निगमों में 23 और 2 नगर पालिका परिषद में 2 चलित रसोई केन्द्र संचालित हो रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा चलित रसोई केन्द्र की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य स्थल पर ही किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाये। प्रदेश में चलित रसोई केन्द्र के वाहनों और उपकरणों की एकरूपता के लिये नगरीय प्रशासन संचालनालय ने सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इसी के साथ दीनदयाल रसोई योजना के लिये नगरीय निकायों को अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के विस्तार के लिये 68 नवीन रसोई घरों के संचालन का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये राज्य शासन को भेजा गया है।

धार्मिक नगरों में रसोई केन्द्र

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 6 धार्मिक नगरों मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में भी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया है। नगरीय निकायों द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली थाली में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।

भोपाल में सड़क धंसने पर पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट

नाले पर पुलिया नहीं बनाई, उसे कर दिया अंडरग्राउंड, उसी में निगम ने टॉयलेट भी बना दिया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एमपी नगर में सड़क धंसने पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने अपनी रिपोर्ट दी है। जिसमें कहा गया कि एमपी नगर की बसाहट के दौरान करीब 50 साल पहले पत्थरों की दीवार का नाला बना था। उस समय इसके ऊपर पुलिया नहीं बनाई गई, बल्कि उसे अंडरग्राउंड कर दिया गया। कुछ साल पहले निगम ने नाले के ऊपर ही पब्लिक टॉयलेट बना दिया। सफाई नहीं होने और पानी के प्रेशर के कारण सड़क धंस गई। चीफ इंजीनियर मस्के ने बताया, सड़क की मरम्मत शुरू कर दी गई है। अगले 48 घंटे यानी, शनिवार तक नाले पर निर्माण पूरा कर देंगे। अंदर लोहे के बड़े एंगल से सेंटरिंग की जा रही है। ताकि, मजबूती मिल सके। ऊपर से सीमेंट क्रांकीट का स्लैब डाला जाएगा। बाद में इस सेंटरिंग को नहीं निकालेंगे।

2002 में पीडब्ल्यू को सौंपा था नाला- चीफ इंजीनियर मस्के ने बताया, यह नाला लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग क्रमांक-2 भोपाल के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) ने किया था। जिसे साल 2002 में पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया था।

मार्ग के बाईं ओर ज्योति टॉकीज के पास स्थित लगभग 50 वर्ष पुराना पत्थर की दीवारों से निर्मित और अंडरग्राउंड नाला है। समय के साथ इस नाले के दोनों छोरों को नगर निगम ने कवर कर दिया। वहीं, अपस्ट्रीम हिस्से पर एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण भी कर दिया गया है। इस कारण नाले की न तो सफाई हो सकी और न ही निरीक्षण हो सका। हर साल बारिश में यह नाला सफाई से रह जाता, जबकि निगम का फोकस अन्य नालों पर रहता है।

कई इलाकों का आता है पानी

यह नाला एमपी नगर जोन-1 से जोन-2 की ओर जल निकासी के लिए बना है। इसके अपस्ट्रीम की ओर बाईं दिशा से जुड़ी एक छोटी नाली का पानी भी इसी मुख्य नाले से आता है। दीवार पर दबाव बढ़ने के कारण उसकी संरचना प्रभावित हुई और मार्ग के एक हिस्से में गड्ढा बन गया।

पारे के खतरों से बचने थर्मामीटर व बीपी मशीन को कहें अलविदा

भोपाल। लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारे युक्त चिकित्सा उपकरणों – जैसे थर्मामीटर और रक्तचाप मापक यंत्र – के उपयोग को पूरी तरह बंद करने की अपील आज उपभोक्ता संगठनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों और पर्यावरणविदों द्वारा की गई। यह अपील कंज़्यूमर वॉयस और नेशनल सेंटर फ़ॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान की गई, जिसमें घरेलू स्तर पर खासकर बच्चों और महिलाओं में पारे के दुष्प्रभाव और मिनामाटा कन्वेंशन में भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई।

पारे युक्त उपकरण, जब तक टूटे नहीं होते, सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन एक बार टूटने या गलत तरीके से फेंके जाने पर, पारा वाष्पित होकर जहरीली गैस के रूप में वातावरण में फैलता है, जो श्वसन या त्वचा के संपर्क से मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। इससे फेफड़े, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है। पारा वातावरण, मिट्टी और जल को प्रदूषित कर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है और व्यापक जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। टॉक्सिक्स लिंक की 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष लगभग 8 टन पारा चिकित्सा मापन उपकरणों से निकलता है, जिसमें से 69 प्रतिशत स्फिग्मोमैनोमीटर के गलत निपटान से आता है।

डॉ. प्रदीप नंदी, निदेशक, एनसीएचएसई, ने कहा, भारत, मिनामाटा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने चिकित्सा उपकरणों से पारे को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रतिबद्धता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पारे को शीर्ष 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रसायनों में शामिल किया है। कम मात्रा में भी यह तंत्रिका, पाचन और प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, खासकर बच्चों में।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वैज्ञानिक डॉ. पी. के. श्रीवास्तव ने कहा, हमें पारे के रिसाव को रोकने के लिए अस्पतालों के साथ-साथ घरों में भी सख्त प्रबंधन प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए और पारे रहित डिजिटल विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। आज की जिम्मेदारी, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। डॉ. ए. के. चौधरी, चिकित्सा निदेशक, जे. के. हॉस्पिटल, भोपाल ने कहा, महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए पारे का संपर्क जानलेवा हो सकता है। पारे युक्त थर्मामीटर और बीपी मशीन को हटाकर डिजिटल उपकरणों को अपनाना न केवल जीवन रक्षक है, बल्कि यह पर्यावरण की भी रक्षा करता है।

अन्य वक्ताओं में डॉ. नलिनी मिश्रा (डीन, एलएन सिटी यूनिवर्सिटी), डॉ. अजीत सोनी (रजिस्ट्रार, एलएन सिटी), और डॉ. सरला मेनन (मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जे. के. हॉस्पिटल) शामिल थीं। सभी ने डिजिटल विकल्पों की ओर संक्रमण और कचरा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कंज़्यूमर वॉयस की प्रोजेक्ट हेड (फूड एंड न्यूट्रिशन), नीलांजना बोस ने कहा, डिजिटल उपकरण न केवल सटीक हैं, बल्कि सुलभ और किफायती भी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र ने इसकी शुरुआत कर दी है – अब हर घर को इन उपकरणों को अपनाना चाहिए।

जे के हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में आयोजित इस कार्यशाला में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें युवा, महिलाएं, उपभोक्ता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे।

विकास और पर्यावरण संतुलन एक साथ आवश्यक : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विकास और पर्यावरण संतुलन एक साथ आवश्यक हैं। सुखद, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के पुनीत कार्य में सभी की सहभागिता ज़रूरी है। पौधारोपण व्यक्ति को जीवन और प्रकृति के बीच आत्मीय संबंध की गहरी अनुभूति भी कराता है। प्रदेश में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना के लिए मीडिया समूह के 'एक पेड़, एक ज़िंदगी' अभियान की उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सराहना की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह अभियान हरियाली बढ़ाने में सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मीडिया समूह द्वारा जनसामान्य को तुलसी के बीज वितरित कर आयुर्वेदिक परंपरा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को भी सशक्त किया जा रहा है। यह नवाचार न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली भूमिका निभाई है। मध्यप्रदेश में 'जल-गंगा संवर्धन अभियान', 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति वृक्षारोपण को अपनी भावनाओं और स्मृतियों से जोड़ता है, तो उसका संरक्षण भी स्वाभाविक रूप से होता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण और विकास विरोधी तत्व नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जितना आवश्यक अधोसंरचना, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास है, उतना ही महत्वपूर्ण स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरियाली को संरक्षित रखना भी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों से जुड़ें और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

संपादकीय

राज्यसभा : सियासी नामांकन!

उच्च सदन राज्य सभा में केन्द्र सरकार की सलाह पर 12 सदस्यों के नामांकन के पीछे संविधान निर्माताओं को मूल उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभाशाली और निष्पक्ष लोगों को संसद में लाने का था, जो चुनावी राजनीति से अलग हों तथा लोकसभा में चुनकर नहीं पहुंच सकते। कमोबेश 11 साल पहले तक इसी परंपरा का पालन भी होता रहा। इक्का-दुक्का अपवाद रहे। लेकिन उसके पीछे भी ऐसे नामांकनों का सीधा राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं रही। अलबत्ता परोक्ष रूप जितना लाभ मिल सके, लिया जाता था। उदाहरण के लिए सचिन तेंडुलकर को विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद जिस फुर्ती से राज्यसभा की सांसदी सौंपी गई, उसका उद्देश्य सचिन की युवाओं में लोकप्रियता का राजनीतिक लाभ लेना था। सचिन किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य न तो थे और न ही हैं। इन नामांकनों का उद्देश्य भी यही था कि अकादमिक और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों की आवाज भी सदन में सुनाई दे। हालांकि इसमें राजनीतिक झुकाव का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता था। कुल मिलाकर कोशिश यही रहती थी कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, विज्ञान, साहित्य,समाज सेवा, खेल आदि की यशस्वी विभूतियों को लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ताकि सदन की बौद्धिक पूंजी समृद्ध हो। लेकिन मोदी राज में इस परंपरा को तिलांजलि दे दी गई लगती है। हाल में मोदी सरकार द्वारा नामजद 4 लोगों के नामांकन देखकर यही लगता है कि अब राजनीतिक विचारधारा और इस नामजदगी से होने वाले सियासी लाभ को देखकर ही ये नामांकन किए गए हैं। यानी सत्ता पक्ष का दबदबा वहां भी रहे। इस हिसाब यूपीए और कांग्रेस तो छोड़िए पूर्व की वाजपेयी सरकार की नीति से भी मोदी सरकार की नीति अलग दिखाई पड़ती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां पहले यह श्रेणी निष्पक्ष उत्कृष्टता को दर्शाने वाला मंच मानी जाती थी, अब इसका उपयोग चुनावी फायदे के लिए वैचारिक और राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। साथ ही अपना भौगोलिक प्रभाव भी बढ़ाया जा सके। केरल से सदानंदन मास्टर का नामांकन इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। बेशक सदानंदन ने अपनी राष्ट्रवादी वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए असाधारण संघर्ष किया और दोनों पैर तक गंवाए। वो केरल में आरएसएस पर वामपंथियों के खूनी हमले के प्रतीक हैं। लिहाजा माकपा और कांग्रेस दोनों ने इस नियुक्ति की आलोचना की है। सदानंदन मास्टर के अलावा जो तीन नाम और नामांकित हुए हैं, वो हैं-जाने माने वकील उज्ज्वल निकम, प्रख्यात इतिहासकार मीना कुमारी जैन और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। माना जा रहा है कि निकम, जो प्रसिद्ध वकील महेश जेठमलानी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। वो आगामी संसद सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने में भाजपा की मदद कर सकते हैं, खासकर जब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे नेता राज्यसभा में मौजूद हैं। इतिहासकार जैन, जो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ी हैं और वामपंथी इतिहासकारों के खिलाफ वैचारिक मोर्चे पर सक्रिय रही हैं, सदन में इतिहास और संस्कृति पर बहसों को अकादमिक समर्थन देंगी। अयोध्या पर उनकी किताब को अयोध्या विवाद के कानूनी मामले में बार-बार उद्धृत किया गया। श्रृंखला पिछले 11 वर्षों में पहले ऐसे राजनयिक हैं जिन्हें नामित किया गया है, और उन्हें उनके पूर्व कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है। अब अगर अटलजी के जमाने से इसकी तुलना करें तो एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वाजपेयीजी ने 1998 से 2003 के बीच 11 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया, जिनमें–मशहूर गायिका लता मंगेशकर, अभिनेत्री हेमा मालिनी और दारा सिंह, दो पत्रकार–नवभारत टाइम्स के तत्कालीन संपादक विद्यानिवास मिश्र और 'द' पायोनियर के संपादक चंदन मित्रा को नामजद किया।

किसानों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य'

नजरिया

अरविंद सरदाना

लेखक 'एकलव्य फॉउन्डेशन' के पूर्व-निदेशक हैं।

'एमएसपी' कानून को अव्यावहारिक बताने वाले तर्क देते हैं कि यदि इसे क़ानूनी स्वरूप दिया गया तो सरकार को विवश होकर मंडियों में आने वाली अधिकांश फसलें खरीदना होंगी। यह आर्थिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए सरकार 'एमएसपी' को व्यापक नहीं बनाना चाहती और न ही वह उसे एक क़ानूनी हक़ बनाना चाहती है। यह एक भ्रमित करने वाला तर्क है। 'एमएसपी' का प्रस्तावित कानून है कि यदि मंडियों में औसत भाव (मॉडल प्राइस) 'एमएसपी' से कम हैं, तब सरकार को खरीदना होगा। सरकार फसल को गुणवत्ता के नियमानुसार उपार्जन की व्यवस्था कर सकती है या 'एमएसपी' और मंडी भाव में अंतर का मुआवजा दे सकती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) पर देश में लम्बे समय से चर्चा होती आ रही है और इसके क़ानूनी हक़ की कोशिश भी की जाती रही है। कहा जा रहा है कि कानून बनने के बाद ही किसानों को उनकी उपज का 'एमएसपी' पूरी तरह हासिल हो सकेगा, लेकिन सरकार की ओर से इसे कानूनी जामा पहनाने में झिझक दिखाई दे रही है। सरकार की इस झिझक से महसूस होता है कि अनकहे रूप से इससे इनकार किया जा रहा है।

'एमएसपी' कानून को अव्यावहारिक बताने वाले तर्क देते हैं कि यदि इसे क़ानूनी स्वरूप दिया गया तो सरकार को विवश होकर मंडियों में आने वाली अधिकांश फसलें खरीदना होंगी। यह आर्थिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए सरकार 'एमएसपी' को व्यापक नहीं बनाना चाहती और न ही वह उसे एक क़ानूनी हक़ बनाना चाहती है। यह एक भ्रमित करने वाला तर्क है। 'एमएसपी' का प्रस्तावित कानून है कि यदि मंडियों में औसत भाव (मॉडल प्राइस) 'एमएसपी' से कम हैं, तब सरकार को खरीदना होगा। सरकार फसल को गुणवत्ता के नियमानुसार उपार्जन की व्यवस्था कर सकती है या 'एमएसपी' और मंडी भाव में अंतर का मुआवजा दे सकती है।

अनुभव से देखा गया है कि कई फसलों में 10 से 35 प्रतिशत उपार्जन से मंडी भाव 'एमएसपी' के करीब आ जाता है। यह तभी संभव होता है जब उपार्जन के केंद्र गाँव के करीब बनाए जाएँ, किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाये, समय पर केंद्र शुरू हों और समय पर भुगतान हो। ज़रूरत अनुसार मंडी में ही केंद्र बनाए जाएँ। सरकार कुछ फसलों जैसे गेहूँ, धान, कपास के लिए पुख्ता व्यवस्था बनाती है, पर बाकी के लिए व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। उपार्जन व्यापक रूप से, कुछ ही राज्यों में किया जा रहा। 'एमएसपी' कानून का लक्ष्य है कि इसी प्रकार की व्यवस्था सभी 23 फसलों के लिए हो और सभी राज्यों में कायम हो।

उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में गेहूँ के लिए 4500 से अधिक उपार्जन केंद्र बनाए गए और हर जिले में कलेक्टर को व्यवस्था बनाने की जवाबदारी दी गई। उसी प्रकार वर्ष 23-24 में 'भारतीय कपास निगम' ने कपास के लिए 11 राज्यों के 145 जिलों में 450 से अधिक 'उपार्जन केंद्र' बनाए और सभी प्रमुख मंडियों को कवर किया। तभी भाव को नियंत्रण करने और 'एमएसपी' के करीब लाने में सफल रहे। इसकी तुलना दलहन एवं तिलहन से करने पर समझ आता है कि यहाँ व्यवस्था बहुत कमज़ोर है और व्यापक नहीं है। मंडी भाव 'एमएसपी' से कम ही रहते हैं।

उपार्जन की व्यापक व्यवस्था के कारण किसानों के पास केंद्र पर जाकर 'एमएसपी' भाव पर बेचने का ठोस विकल्प बन जाता है। इसी कारण मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी और भाव 'एमएसपी' के निकट आया।

अन्य फसलों में यह व्यापक व्यवस्था नहीं की गई और उपार्जन भी सीमित रखा गया।

उपार्जन के दो मुख्य लक्ष्य हैं, एक - सरकार की खाद्य योजनाओं के लिए खाद्यान जुटाना और दूसरा मंडी भाव को नियंत्रित करना। खाद्य योजनाएँ प्रमुख रूप से धान और गेहूँ पर निर्भर हैं। 'भारतीय खाद्य निगम' (एफसीआई) का 95 प्रतिशत स्टॉक इन दो फसलों से भरा होता है। 'एमएसपी' की सूची में आने वाली अन्य फसलों, जैसे तिलहन, दलहन, मोटे अनाज खाद्य योजनाओं में बहुत मामूली रूप से शामिल किए गए हैं। इस कारण सरकारी 'नाफेड' (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) जैसी संस्था भी सीमित खरीदारी करती है। इससे मंडी के भाव पर प्रभाव नहीं पड़ता और यह आम तौर पर 'एमएसपी' से कम ही रहता है।

दूसरी तरफ, मंडी भाव को नियंत्रण करने का लक्ष्य 'नाफेड' के नियमों में लिखा है, पर उसे धरातल पर उतारने की व्यापक व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे एक अनकहा संकोच है। मंडी भाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकारी ज़रूरत से अधिक स्टॉक हो सकता है। तब उसकी व्यवस्था कैसे करें और बाज़ार में पुनः बेचने पर जो घाटा हो सकता है उसकी भरपाई कौन करेगा। इस स्थिति से बचने के लिए 'नाफेड' कम उपार्जन करती है। 'एमएसपी' को क़ानूनी जामा पहनाने पर यह साफ होगा कि घाटे की भरपाई सरकार करेगी, क्योंकि भाव को नियंत्रण करना उसका सामाजिक दायित्व है।

हम अन्य फसलों, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, उड़द, तुवर, मूंग, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल आदि सभी 23 फसलों, जिनका 'एमएसपी' घोषित किया जाता है, के लिए इसी भाव नियंत्रण की अपेक्षा करते हैं। यह क़ानूनी दर्जा मिलने पर किसी भी सरकार को पूरा करना होगा। यह किसानों का हक़ है कोई सौगात नहीं।

इसके लिए हर फसल के मुख्य इलाकों में, जिला स्तर पर, उपार्जन की व्यापक व्यवस्था बनानी होगी। इसके साथ मंडी में भी सुधार लाना होगा। कई राज्यों में मंडी बहुत कमज़ोर हालत में हैं। फसल बिक्री के लिए किसान बिचौलियों की एक लम्बी कड़ी पर निर्भर हैं। किसान सीधे मंडी में खुली नीलामी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक सरकारी रपट के अनुसार देश में 7057 मंडियाँ है, पर इनकी ज़रूरत कहीं अधिक है। वर्तमान में हर 400 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है, जबकि 80 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए। बाजार में आने वाली फसल और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से राज्यों को इसका विस्तार तय करना चाहिए। 'एमएसपी' कानून तभी कारगर हो सकता है जब मंडी व्यवस्था और उपार्जन की व्यवस्था दोनों सुचारू हों और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में खड़े रहें। जब तक यह व्यवस्था नहीं बनती, वहां 'भावान्तर फार्मूले' से किसानों को मुआवजा दिया जाए।

एक और बात 'एमएसपी' को कानूनी बनाने से रोकती है- उसके अनुसार 'एमएसपी कानून को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका खर्चा कोई भी सरकार नहीं उठा पायेगी।' पर खर्च का अनुमान गलत अवधारणा पर तय किया गया है। सरकार को फसल का उपार्जन एक सीमित मात्रा में ही करना है, जो कि 10 से 35 प्रतिशत होगा। उपार्जन का एक हिस्सा खाद्य योजनाओं के लिए होता है। यह खर्च खाद्य-सुरक्षा के लिए है जिसे नहीं जोड़ना चाहिए। 'एमएसपी' कानून का खर्च वह है जो भाव नियंत्रण के लिए किसानों को मुआवजा देने पर खर्च होता हो।

'एमएसपी' कानून लागू करने से कृषि में कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। कुछ फसलों पर से फोकस हटकर 'एमएसपी' सूची की बाकी फसलों पर उपार्जन की प्रक्रिया होगी। इससे मिश्रित खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। खाद्य-सुरक्षा के लिए मोटे अनाजों को, जो अत्यंत पौष्टिक हैं, शामिल किया जाना चाहिए। गेहूँ और धान के अलावा अन्य फसलों पर भी शोध केन्द्रित होगा। दलहन और तिलहन के लिए देश में पैदावार बढ़ सकती है। इस समय विडम्बना है कि अपनी आपूर्ति के लिए हम किसानों को प्रोत्साहन कम कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर हैं। यह आत्मनिर्भरता का कैसा रास्ता है! 'एमएसपी' की वर्तमान सूची, सभी कृषि उपज का एक छोटा हिस्सा है। क़ानूनी हक़ मिलने पर सभी वन एवं कृषि उपज के लिए उचित मूल्य की मांग उठेगी और इससे एक बड़े वर्ग को सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। (सप्रेस)

पंच परिवर्तन से बदल जाएगा समाज का चेहरा-मोहरा

रास्वसं के शताब्दी वर्ष पर विशेष

प्रो. संजय द्विवेदी

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

इतिहास के चक्र में किसी सांस्कृतिक संगठन के सौ साल की यात्रा साधारण नहीं होती। यह यात्रा बीज से बिरवा और अंततः उसके वटवृक्ष में बदल जाने जैसी है। ऐसे में उस संगठन के भविष्य की यात्रा पर विमर्श होना बहुत स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प भविष्य के भारत की रचना में सहयोगी बन सकते हैं।

अपने शताब्दी वर्ष में संघ ने 'पंच परिवर्तन' का संकल्प लिया है। यह पंच परिवर्तन क्या है? इससे क्या होने वाला है? इसे भी जानना जरूरी है। संघ की मान्यता है कि व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब भारत की व्यवस्थाएं 'स्व' पर आधारित हों। 'स्व' आधारित तंत्र बनाना साधारण नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर देश के तमाम विचारक और राजनेता 'स्व' की बात करते रहे,किंतु व्यवस्था ने उनके विचारों को अप्रासंगिक बना दिया। समाज परिवर्तन के बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं, इसे भी सब मानते हैं। वैचारिक संभ्रम इसका बहुत बड़ा कारण है। हम आत्मविस्मृति के शिकार और आत्मदैन्य से घिरे हुए समाज हैं। गुलामी के लंबे कालखंड ने इस दैन्य को बहुत गहरा कर दिया है। इससे हम अपना मार्ग भटक गए। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर हमें वह रास्ता बताते हैं जिनपर चलकर हम अपनी कुरीतियों से मुक्त एक सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी समाज बन सकते थे। किंतु अंग्रेजों के बाद सत्ता में आए नायकों ने सारा कुछ बिसरा दिया। उस आरंभिक समय में भी दीनदयाल उपाध्याय और डा. राममनोहर लोहिया जैसे नायक भारत की आत्मा में झांकने का प्रयास करते रहे किंतु सत्ता की राजनीति को वे विचार अनुकूल नहीं थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का जो संकल्प लिया है,वह भारत की चिति और उसकी स्मृति को जागृत करने का काम करेगा। राष्ट्रीय चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए 1.नागरिक कर्तव्य, 2. स्वदेशी, 3. पर्यावरण संरक्षण, 4.समरसता, 5.कुटुंब प्रबोधन जैसे पांच संकल्प ही पंच परिवर्तन के सूत्र हैं। इन विषयों में भारत की आत्मा को झकझोरकर जगाने और 'नया भारत' बनाने का संकल्प झलकता है। 'नागरिक कर्तव्यबोध से नवचेतन का संचार'- किसी भी राष्ट्र और लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की सहभागिता और कर्तव्यबोध से ही सार्थक होती है। एक जीवंत लोकतंत्र की गारंटी उसकी नागरिक चेतना ही है। कानूनों की अधिकता और उसे न मानने का मानस दोनों साथ-साथ चलते हैं। अपनी माटी के प्रति प्रेम, उत्कट राष्ट्रभक्ति ही सफल राष्ट्र का आधार है। जापान जैसे देशों का उदाहरण देते समय हमें देखना होगा कि क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना और संवेदना वही है जो एक जापानी में है। आखिर क्या कारण है कि अपनी महान परंपराओं, ज्ञान परंपरा के बाद भी हम एक लापरवाह और कुछ मामलों में अराजक समाज में बदलते जा हैं। कानूनों को तोड़ना यहां फैशन है। यहां तक की हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और सड़कों पर रेड लाइट का उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आते। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, किंतु हैं बहुत बड़ी। चुनावों में शत प्रतिशत मताधिकार तो दूर का सपना है। बहुत शिक्षित शहरों में वोटिंग 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाती। ये सूचनाएं बताती हैं कि हमें अभी जागरूक नागरिक या सजग भारतीय होना शेष है। कानूनों का पालन, कर का समय पर भुगतान, सामाजिक और सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा जरूरी है। एक शानदार समाज की पहचान है कि वह अपने परिवेश को न सिर्फ स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करता है बल्कि अपने प्रयासों से अन्यों को भी प्रेरित करता है। देखा जाता है कि हममें अधिकार बोध बहुत है किंतु कर्तव्यबोध कई बार कम होता है। जबकि संविधान हमें मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी सीख देता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें नागरिकता और सामाजिक आचरण का पाठ पढ़ाते हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं।

सामाजिक समरसता से बनेगी सुंदर दुनिया–सामाजिक समरसता के बिना कोई भी राष्ट्र अग्रणी नहीं बन सकता। गुरु घासीदास कहते हैं- 'मनखे-मनखे एक हैं।' किंतु जातिवाद ने इस भेद को गहरा किया है। तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी हम इस रोग से मुक्त नहीं हो सके हैं। भेदभाव ने हमारे समाज को विभाजित कर रखा है, जिसके चलते दुनिया में हमारी छवि ऐसी बनाई जाती है कि हम अपने ही लोगों से मानवीय व्यवहार नहीं करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे- 'अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है।' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे पू. बालासाहब देवरस ने इस संकट को रेखांकित करते हुए बसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि- 'अगर छूआछूत गलत नहीं है दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, इसे मूल से नष्ट कर देना चाहिए।' ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी सैकड़ों सालों से परंपरा के नाम पर चल रहा है वह हमारा धर्म नहीं है। इतिहास में हुए इन पृष्ठों का कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र इससे अलग हैं। हमारे ऋषि और ग्रंथों के रचयिता सभी वर्गों से हैं। भगवान बाल्मीकि और वेद व्यास इसी परंपरा से आते हैं। यानि यह भेद शास्त्र आधारित नहीं है। यह विकृति है। इससे मुक्ति जरूरी है।हमें इसके सचेतन प्रयास करते हुए अपने आचरण, व्यवहार और वाणी से समरसता का अग्रदूत बनना होगा। सभी समाजों और वर्गों से संवाद और सहकार बनाकर हम एक आदर्श समाज की रचना में सहयोगी हो सकते हैं। इससे समाज का सशक्तिकरण भी होगा। समानता का व्यवहार, वाणी संयम, परस्पर सहयोग, संवेदनशीलता से हम दूरियों को घटा सकते हैं और भ्रम के जाले साफ कर सकते हैं। साथ ही अपने गांव, नगर के मंदिर, जलश्रोत, श्मशान सबके लिए समान रूप से खुल होने ही चाहिए। इसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए।

हमारी शक्ति है 'कुटुंब'– आज का सबसे बड़ा संकट कुटुंब का बिखराव है। एकल परिवारों में बंटते जाना और अकेले होते जाना इस समय की त्रासदी है। जबकि कल्याणकारी कुटुंब वह है जहां सब संरक्षण, स्नेह और संवेदना के सूत्र में बंधे होते हैं। जहां बालकों को प्यार और शिक्षा, वयस्कों को सम्मान और बुजुर्गों को सम्मान और सेवा मिलती है। परिवार हमारी शक्ति बनें इसके लिए पंच परिवर्तन का बड़ा मंत्र है- कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब की एक परंपरा होती है। हम उसे आगे बढ़ाते हैं और संरक्षित करते हैं। मूल्य आधारित जीवन इससे ही संभव होता है। परिवार के मूल्यों से ही बच्चों को संस्कार आते हैं और वे सीखते हैं। जैसे देखते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। कुटुंब दरअसर रिश्तों का विस्तार है। जिसमें पति-पत्नी और बच्चों के अलावा हमारे सगे-संबंधी भी शामिल हैं। उनके सुख में सुख पाना, दुख में दुखी होना और उन्हें संबल देना हमें मनुष्य बनाता है। इसके लिए बच्चों के साथ-साथ रिश्तों को समय देना जरूरी है। औपचारिक और अनौपचारिक रुप से कार्यक्रमों, खान-पान, उत्सवों के माध्यमों से ये रिश्ते दृढ़ होते जाएं यह बहुत जरूरी है।

पंच परिवर्तन के साधारण दिखने वाले सूत्रों में ही भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। इन सूत्रों को अपनाकर हम एक सुंदर बनाने की दिशा में बड़ा काम कर सकते हैं। संघ की शताब्दी वर्ष में लिए गए ये संकल्प हमें एक समाज और राष्ट्र के रूप में संबल देने का काम करेगें इसमें दो राय नहीं है। 22 जनवरी,2024 को अयोध्या में राममंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य की ओर हम बढ़ चले हैं। राम राज्य के मूल्य हमारे जीवन में आएं। परिवारों में आएं। इससे एक सबल, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत बनेगा। आचरण की शुचिता से आए परिवर्तन ही स्थाई होते हैं। इससे ही हमारे मन में राम रमेंगें और देश में रामराज्य आएगा।

क्या हम लोकतंत्र में अप्रशिक्षित हैं?

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बाद हमने बंधुता के मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र का सपना देखा। हमने अपनी सरकार चुनने के लिए अपने मत का अधिकार संविधान में स्थापित किया और इस अभिलाषा से भर उठे कि सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। पचहत्तर साल से ज़्यादा समय बीत गया पर यह सपना अब तक पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। हमारे राजनीतिक दल भेदभाव की खाईयॉं पूरने की बातें तो खूब करते रहते हैं पर उनका जनाधार जात-पॉंत और कौमपरस्ती की सीमाओं में ही क़ैद है। वे ख़ुद ही धर्म और मज़हब के दो पाटों के बीच पिस रहे हैं और हमें भी पीस रहे हैं। यह राजनीतिक चक्की उनके वोट बैंक को भरती है और उनके मुफ़्त के वोट बटोरू दलीय आश्वासनों के कारण देश के राजकोष और साधनों को बड़ी हानि भी पहुँचा रही है। हमारे राजनीतिक दल जिन बेबस और असहाय लोगों के मताधिकार से सरकार बनाने के प्रपंच को अब तक रचते आये हैं उससे उन पीछे रह गये लोगों का कोई भला नहीं हुआ।

यह राजनीतिक दृश्य देखकर लगता है कि हमारे राजनीतिक दल ही लोकतंत्र में अप्रशिक्षित रह गये और हमें भी लोकतंत्र में प्रशिक्षित नहीं कर पाये। वे सिर्फ़ स्वार्थपूर्ति और अधिकारों की मॉंग को प्रोत्साहन देते हैं पर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा निभाये जाने वाले कर्तव्यों की कोई चर्चा भी नहीं चलाते। जनमत को तरह-तरह के लोभ में उलझाकर उसे किसी तरह हथिया लेने की प्रवृत्ति ही हमारी राजनीति के क्षेत्र में सिर चढ़कर बोल रही है। यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की भागीदारी घटती जा रही है और व्यापारिक निजी क्षेत्र राजनीति को अपनी गिरफ़्त में लिये चला जा रहा है। ग़रीबी मुफ़्त अनाज पर पल रही है और बेसहारा लोगों को काम देने की बजाय मुफ़्त पैसा बॉंटकर उन्हें लोकतंत्र में अपनी निर्माणकारी भूमिका निभाने से वंचित किया जा रहा है।

हम देख रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दल ही लोकतंत्र की विफलता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ठहरते हैं। वे कई तरह की जात-बिरादरियों को संतुष्ट करते हुए अब ख़ुद ही थके-हारे लगने लगे हैं। अब उन्हें जात-पांतियों की सेनाओं का भी सामना करके उनको अपने पक्ष में किसी तरह थामे रहना पड़ता है। वे पुराने और नये बनते स्वार्थी गिरोहों से कई प्रकार के समझौतों में अपने ही दल की लोकतांत्रिक पहचान को मिटा रहे हैं। एक-दूसरे पर दोष मढ़ते टूटे-बिखरे लोगों के तथाकथित नेताओं को अपने अपराध छिपाने के लिये भी तो कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटने में कितना समय गॅंवाना पड़ता है। फिर उनके पास वह समय ही कहॉं बचता है जिसमें थोड़ी देर बैठकर वे समूचे राष्ट्र की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के बारे में सोच सकें। लगता है कि इन विषयों पर विचार करने का समय ही उनके पास नहीं है। हम उन्हें केवल चुनाव जीतने की हड़बड़ी में रोज़ भागता-दौड़ता देखते हैं। राजनीतिक दलों के कारनामे देखकर लगता है कि सत्ता पाने के लिये उनके नेताओं के बीच कोई प्रतियोगिता चल रही है और जिस जनता से उन्हें राजकाज चलाने की शक्ति मिलती है वह जनता अपने ही नेताओं से पिछड़ रही है बल्कि नेता ही उसे हरा रहे हैं।

देश के जन लोकतंत्र में प्रशिक्षित हों और निर्दोष प्रतिनिधियों को चुन सकें, यह ज़रूरी काम कोई राजनीतिक दल करना ही नहीं चाहता। राजनीतिक दलों का स्वार्थ साधने वाले दोषी लोग सजा काटते हुए भी चुनाव जीत लेते हैं। उनके दोष सिद्ध होने में कई साल बीत जाते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, चुनाव हो जाने के बाद दलीय हाईकमान के अनधिकृत हस्तक्षेप से सरकार बनायी जाती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कभी विधान मण्डल का नेता नहीं चुन पाते! इस दलीय हाईकमान का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। चुनाव जीत लेने के बाद गठबंधन की माला गूँथने में इस स्वयंभू हाईकमान को कई हफ्ते लग जाते हैं। तब तक राजकाज ही स्थगित बना रहता है।

हमारा लोकतंत्र हम लोगों के लिये, हम लोगों के द्वारा, हम में ही आत्मार्पित है। पर देखने में यही आ रहा है कि वह राजनीतिक दलों के लिये, राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक दलों को ही समर्पित हो गया है। संविधान लोगों और उनके नेताओं से यह अपेक्षा करता है कि वे देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर वह योग्यता अर्जित करें जो उन्हें लोकतंत्र में जिम्मेदारी निभाने के लिए नागरिक अधिकार प्रदान करती है। पर ख़बरें तो कुछ और ही आ रही हैं, विधायक चाहे जब प्रशासकों को पीट रहे हैं। प्रशासक लोगों को पीट रहे हैं और गुस्से से भरे जा रहे लोग भी एक-दूसरे को पीट रहे हैं। आपस में एक-दूसरे पर दोष मढ़कर अपनी विफलताओं को छिपाते राज और समाज को देखकर लगता है कि वह अभी लोकतंत्र को सॅंवारने में प्रशिक्षित ही नहीं हो पाया है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पुल ही तो गिरा है....

व्यंग्य

भूपेन्द्र भारतीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

देश में पुल गिर रहे हैं। क्या हुआ, पुल ही तो गिर रहे हैं। जब पहाड़ तक गिर रहे हैं तो फिर पुल किस आसमान की चिड़िया। बादल तक गिरकर फट रहे तो फिर पुल पर हंगामा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी व्यवस्था को फायदा ही होगा। फिर नये पुल बनेंगे। टेंडर होगे। मंत्रालय जीवंत रहेंगे। ठेकेदारों को काम मिलेगा। बिचौलियों को माल और गरीब को रोजगार मिलेगा। देखो कितना अच्छा होता है पुल गिरना। संसद में विपक्ष को पुल गिरने के लिए बहस का विषय मिलता है। लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए पुल को गिरने के लिए ही बनाया जाना चाहिए। ओर बनते ही आ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो विश्व में पुल गिरने के मामले में हम नंबर वन है।

पुल के गिरने से ज्यादा ढह जाना ओर भी रोचक घटना होती है। यहां पुल का ढह जाना एक नियति में आता है। मैं तो इसे शास्त्र सम्मत मानता हूँ। जो बना है उसे एक दिन ढह ही जाना है। हिन्दी व्याकरण में तो इस क्रिया को ओर सुंदर तरह से परिभाषित किया गया है। 'ढह जाना' एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात् क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। 'ढह जाना' क्रिया में, कर्ता (जैसे कोई इमारत या संरचना) स्वयं ही गिरता है, उसे किसी अन्य वस्तु को गिराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, यह एक अकर्मक क्रिया है। कितनी अच्छी क्रिया है, किसी का दोष नहीं। अपने आप होने वाला कार्य। फिर बेचारी सरकार व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पुल ढह जाने व गिरने पर क्यों बीच में लाया जाता है! ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तो पुल के साथ अकर्मक क्रिया होती है। कोई इसे उसके साथ करता नहीं है। वह बेचारा कमजोर रहता है इसलिए जल्दी ढह जाता है।

हमारे लिए गिरना गर्व का विषय रहा है। देश में पहले सरकारें गिरती थी। अब वह समय चला गया। अब पुल गिरते हैं। भवन गिरते हैं। विमान गिरते हैं। लड़के कोचिंग संस्थानों में गिरते हैं। पापा की परियाँ स्कूटी से गिरती है! मजबूत सरकारों में ऐसा होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा। यह सब मानवीय लापरवाही व गलती के कारण होता है। इसमें सरकारों का कोई हाथ-पैर नहीं होता है, ना ही मंत्रालयों की कोई फाईल। यह सब मानवरूपी अधिकारियों के कारण होता है। ऐसा विभिन्न जाँचों के आंकड़े कहते हैं। 'मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है।' ऐसा कुछ बड़े शायर भी कहते हैं। अब पुल गिरना शुभ घटना में गिना जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि सरकार मजबूत है। लोकतंत्र में सब अच्छा चल रहा है। संविधान अच्छा कार्य कर रहा है। उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। कानून अपनी जगह ठीक है। उसे लचर कहना, अपराध माना जाना चाहिए। जनता ही मूर्ख है जो इन गिरते पुलों पर से निकलती हैं। इनपर चढ़कर सेल्फी लेती। भला यह भी प्रेम करने की कोई जगह है। जनता को गिरते पुल पर से नहीं निकलना चाहिए। उसे पुल के ऊपर से उड़कर पार करना चाहिए। लोकनिर्माण विभाग तो बहुत से पुलों के पास लिखता भी आया है कि यह पुल कब भी गिर सकता है, इसका समय समाप्त हो गया है-सावधान!' फिर भी जनता है कि मानती ही नहीं! उसे गिरते पुल पर से ही निकलने में मजा आता है।

देश में पुलों का गिरना जनता की सरकार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सरकारों को अब पुलों का निर्माण रोक देना चाहिए। इस देश की जनता इस लायक नहीं है। आखिर कब तक कोई सरकार पुल गिरने के कारण बदनाम होती रहे। ऊपर से मीडिया अलग नहीं मानता। वह गिरे हुए पुलों पर भी चढ़कर सरकारों को घेरता है। इधर पुल गिरा नहीं कि मीडियाकर्मी उसपर चढ़े नहीं। वे भी पुल गिरने की प्रतीक्षा में रहते हैं। बताओ यह भी कोई पत्रकारिता हुई! कितने गिरे हुए लोग हैं! ये सरकार के लिए कितनी मुसीबत करते हैं। आखिरकार मीडिया के प्रश्नों से परेशान होकर सरकार को कहना ही पड़ता है - 'पुल ही तो गिरा है..!!'

मुद्दा

डॉ. रमेश ठाकुर
सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार

यूरिया खाद की कमी से परेशान किसान

बेशक, केंद्र सरकार यूरिया की कमी को दूर करने के लिए इस साल के अंत तक यूरिया के आयात को बंद करके नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाइ-अमोनियम फॉस्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के बढ़ावे पर विचार कर रही हो? लेकिन, मौजूदा परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इस पर तत्काल कोई हल निकालना होगा। क्योंकि यूरिया की किल्लत को लेकर देशभर के किसानों में घोर आक्रोश है। विभिन्न जगहों पर आंदोलन जैसे हालात बने हुई हैं। बीती 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर में किसानों और पुलिस के बीच यूरिया को लेकर जमकर विद्रोह हुआ। नौबत ऐसी आई कि किसानों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। घटना के बाद किसान भंयकर गुस्से में है। लखीमपुर ही नहीं, देश के कई हिस्सों में खाद के लिए दुकानों पर किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं।

यूरिया खाद की कमी ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। यूरिया के लिए किसान दर-दर भटक रहे हैं। सेंटरों पर घंटों डेरा डालने व अन्य कोशिशों के बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल रही। सरकार के अधिकृत मंडियों, सेंटरों व समितियों में यूरिया है ही नहीं? हर जगह किल्लत है। जबकि, सरकार का कहना है कि देश में यूरिया की जितनी जरूरत थी उतनी समितियों में भेज दी है। हुकूमती बयान को किसान किल्लत कहें या कालाबाजारी? दरअसल, मानसून के मध्य वाला ये सीजन धान की फसल का होता है। धान का पौधा बगैर यूरिया खाद डले फुटाव नहीं करता। धान की नर्सरी को लईया कहते है जिसकी रोपाई के पहले सप्ताह में यूरिया की जरूरत पड़ती है जो इस समय पूरी नहीं हो पा रही।

बेशक, केंद्र सरकार यूरिया की कमी को दूर करने के लिए इस साल के अंत तक यूरिया के आयात को बंद करके नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाइ-अमोनियम फॉस्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के बढ़ावे पर विचार कर रही हो? लेकिन, मौजूदा परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इस पर तत्काल कोई हल निकालना होगा। क्योंकि यूरिया की किल्लत को लेकर देशभर के किसानों में घोर आक्रोश है। विभिन्न जगहों पर आंदोलन जैसे हालात बने हुई हैं। बीती 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर में किसानों और पुलिस के बीच यूरिया को लेकर जमकर विद्रोह हुआ। नौबत ऐसी आई कि किसानों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। घटना के बाद किसान भंयकर गुस्से में है। लखीमपुर ही नहीं, देश के कई हिस्सों में खाद के लिए दुकानों पर किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं।

नई यूरिया नीति-2015 के मुताबिक वर्तमान में लगभग 283.74 एलएमटी की संस्थापित वार्षिक क्षमता वाली 36 गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयां हैं। पर, इसमें भी अब और वृद्धि की आवश्यकता महसूस होने लगी है। किसानों का आरोप है कि यूरिया की किल्लत के

पीछे कालाबाजारी है। कहने को बाजारों में यूरिया के स्टॉक की कमी है। पर, ब्लैक में कोई जितनी चाहें, उतनी यूरिया ले सकता है। दरअसल, धान के लिए यूरिया सबसे बड़ी जरूरत होती है। पिछले कुछ दशकों से खेती पूर्ण रूप से यूरिया खाद पर निर्भर हो गई है। यूरिया ऐसी खाद है जो किसी भी किस्म की फसल की उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। बेशक सरकारें ऑरगेनिंक फसलों पर जोर देती हों। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है जमीनें अब उतनी ताकतवर नहीं रही, जो बिना यूरिया के फसलें उग सकें। खेतों में इस समय धान की फसल लगी है, उसमें यूरिया नहीं ड़लने से फसल मुरझाने लगी हैं।

कुल मिलाकर, यूरिया की कमी का बिचौलिए और दलाल खूब फायदा उठा रहे हैं। यूरिया की पहली खेप जब सेंटरों पर पहुंची, तभी दलालों ने स्टॉक जमा कर लिए। उन्हें पता था, इस बार भी हर साल की भांति यूरिया के लिए मारामारी मचेगी। किसानों को सरकार के अधिकृत सेंटरों से यूरिया नहीं मिलने पर वह मजबूरन दलालों से दूनी कीमतों पर खरीदने को विवश हैं। उनके सामने 'मरता क्या न करता' जैसी नौबत जो है। यूरिया धान में नहीं डलेगी, तो फसल नष्ट हो जाएगी। किसानों की किल्लत को देखते हुए कुछ प्रमुख किसान संगठन केंद्र सरकार से यूरिया की क्षमता बढ़ाने और सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत में यूरिया की उपलब्धता 280 लाख टन है, जबकि मांग करीब 350 लाख टन यूरिया की है। इस बड़े गैप के चलते ही ऐसी मारामारी हो रही है।

कुछ साल पहले केंद्र सरकार का जोर था कि किसान ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दें? पर, किसान ऐसी सलाहों पर ज्यादा गौर नहीं करते। वह इसलिए कि जमीन में बंजरपन इतना बढ़ गया है कि खादों के इस्तेमाल करने बिना फसलें उग ही नहीं सकती। प्रतीत ऐसा होता है कि हम दूसरी पीढ़ी के लिए खेती लायक जमीन छोड़ेंगे ही नहीं? फसली जमीन को जिंदा रखने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना ही होगा। नहीं तो जमीन खेती के योग्य नहीं बचेगी। पर, अन्नदाता दूरगामी दुष्परिणामों की परवाह किए बिना यूरिया का इस्तेमाल बेहताशा करता है। ये सच्चाई भी उन्हें पता है कि यूरिया के अत्यधिक उपयोग से खेतों की उपज क्षमता लगातार घट रही है। पर उनके सामने खेती करने का कोई दूसरा विकल्प है भी तो नहीं?

किसान केंद्र सरकार से यूरिया की किल्लत दूर करने और सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह रसोई गैस के सिलेंडर का सब्सिडी वाला धन उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होता है। वैसे ही किसान बाजार मूल्य पर यूरिया खरीदे और सब्सिडी की रकम उनके खातां में पहुंचाई जाए। अगर ऐसा होता, तो निश्चित रूप से इस कदम से यूरिया की कालाबाजारी रूकेगी। क्योंकि विगत कुछ वर्षों से यूरिया पर बाजारों में जमकर कालाबजारी बढ़ी है। सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो कालाबाजारी को रोकने में अप्रत्याशित मदद मिलगी। क्योंकि यदा-कदा निजी यूरिया के प्रतिष्ठानों पर सरकारी छापों और यूरिया की बोरियां जब्त करने की तमाम अनगिनत घटनाएं इसकी हिस्सा रही हैं।

ताज्जुब इस बात का है कि सहकारी समितियों पर यूरिया मौजूद होते हुए भी दुकानदार किसानों को मुहैया नहीं कराते। लोकल प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें शिकायतें मिलती हैं कि सहकारी मंडियों और समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन निजी दुकानों पर ऊंचे दाम पर यूरिया मिल जाती है। नेपाल से सटे उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में यूरिया की खुलेआम तस्करी होती है। नेपाल में कई गुना दामों में बिकती है। यूरिया को सुगमता से उपलब्ध करवाने का जिम्मा 'रसायन एंव उर्वरक मंत्रालय' का होता है। 2022-23 में यूरिया का आयात 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया। 2020-21 में यूरिया आयात 98.28 लाख टन, 2019-20 में 91.23 लाख टन और 2018-19 में 74.81 लाख टन था। लगातार हुई इस घटौती ने ही विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। किसान यूरिया के लिए परेशान हो, इसके लिए बिना देर किए कोई हल निकालने की आवश्यकता है।

निर्णय

राज कुमार सिन्हा
बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

आदिवासी महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार ऐतिहासिक

किसी आदिवासी महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को केवल लिंग के आधार पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करना अनुचित और असंवैधानिक दोनों है। इस फैसले ने आदिवासी समुदायों में महिलाओं के समान उत्तराधिकार अधिकारों की पुष्टि की है। इस फैसले ने लंबे समय से चली आ रही धारणा को पलट दिया कि ऐसे अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले रीति–रिवाजों को तब तक अस्तित्व में माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एचएसए), 1956 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं होता, फिर भी अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अपवाद का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि आदिवासी महिलाएं पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हैं। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक कोई विशिष्ट प्रथागत प्रतिबंध सिद्ध न हो जाए, समानता कायम रहनी चाहिए ।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजाति की महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों से जुड़े एक मामले में सुनाया, जिसने अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांगा था।

गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिंग के आधार पर आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है और पैतृक संपत्ति पर उनके समान अधिकार की पुष्टि की है। फैसले में कहा गया है किसी आदिवासी महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को केवल लिंग के आधार पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करना अनुचित और असंवैधानिक दोनों है। इस फैसले ने आदिवासी समुदायों में महिलाओं के समान उत्तराधिकार अधिकारों की पुष्टि की है। इस फैसले ने लंबे समय से चली आ रही धारणा को पलट दिया कि ऐसे अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले रीति-रिवाजों को तब तक अस्तित्व में माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एचएसए), 1956 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं होता, फिर भी अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अपवाद का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि आदिवासी महिलाएं पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हैं। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक कोई विशिष्ट प्रथागत प्रतिबंध सिद्ध न हो जाए, समानता कायम रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजाति की महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों से जुड़े एक मामले में सुनाया, जिसने अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। उनके दावे का परिवार के पुरुष सदस्यों ने विरोध किया और तर्क दिया कि आदिवासी रीति-रिवाज महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और नीचली आदालतों से याचिका खारिज कर दिया गया था। इस फैसले ने आदिवासी समुदायों में महिलाओं के समान उत्तराधिकार अधिकारों की पुष्टि की है। इस फैसले ने लंबे समय से चली आ रही धारणा को पलट दिया है कि ऐसे अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले रीति-रिवाजों को तब

तक अस्तित्व में माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

हाईकोर्ट और निचली अदालतों के निष्कर्षों को पलटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों के दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसमें महिलाओं को उत्तराधिकार की अनुमति देने वाली प्रथा को साबित करने की आवश्यकता बताई गई थी।

पीठ ने कहा कि महिलाओं, जिनमें मुकदमे में शामिल महिलाएं भी शामिल हैं, को उत्तराधिकार से वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण दोनों है। न्यायालय ने आगे कहा कि ज़िम्मेदारी किसी भी मौजूदा प्रथा को साबित करने की है जो पैतृक संपत्ति पर उनके अधिकार को प्रतिबंधित करती है।पीठ ने पहले के फैसलों को खारिज करते हुए कहा कि हमारा दृढ़ मत है कि 'न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 14 के व्यापक प्रभाव के साथ, अपीलकर्ता-वादी, संपत्ति में अपने समान हिस्से के हकदार हैं।' संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म,जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

यह फैसला व्यापक महत्व रखता है क्योंकि यह आदिवासी समुदायों में लैंगिक न्याय के बारे में चल रही बहस पर पुनर्विचार करता है और उसे और पुष्ट करता है, खासकर संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों के अभाव में। हालांकि एचएसए, धारा 2(2) के तहत, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इसके दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा अधिसूचित न करे, सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट किया है कि इस तरह की वैधानिक चुप्पी संस्थागत असमानता का आधार नहीं बन सकती।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 2022 में कमला नेती बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के केस में आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधन करके आदिवासी महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस मत से यह स्पष्ट है कि कोर्ट आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति पर अधिकार देना चाहता है।

ज्ञात हो कि दिसंबर 2024 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को समान उत्तराधिकार का अधिकार देने से परहेज किया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी देते हुए भारत जन आंदोलन के विजय भाई ने कहा कि परम्परा एवं मौलिक अधिकार (संविधान का मूल ढांचा तत्व) के बीच को व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति ने मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी है।यह भी समझना होगा कि कोई भी परम्परा मौलिक अधिकार के विरुद्ध जाता है तो वो परम्परा खारिज हो जाता है। इसलिए आदिवासी परम्परा की जब भी बात करेंगे तो हमारी समतामूलक और सामूहिकता तत्वों के साथ - साथ सबसे पहले 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' को ही प्रधानता देना होगा। आदिवासी समुदाय पर संविधान द्वारा प्रदत अनुच्छेद 13 की दुहाई देते हुए रूढ़ी प्रथा के नाम पर अपनी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक आज़ादी का हनन करने का आरोप भी लगता रहा है। जबकि आदिवासी समुदाय में दूसरे समुदायों से ज्यादा खुलापन है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय, व्याप्त अंधकार में एक किरण की तरह उभरता है, जो आदिवासी समुदाय में हलचल पैदा करेगा।

पुस्तक समीक्षा

वंदना अवस्थी
समीक्षक

रोमांचक संस्मरणों की गाथा 'अमरीका जैसा मैंने देखा'

'अमरीका जैसा मैंने देखा' यह पुस्तक कविता की अमरीका यात्रा के शानदार संस्मरणों से भरी-पूरी है। पुस्तक में लगभग सभी संस्मरण, अमरीका के विभिन्न शहरों की संस्कृति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। पुस्तक के पहले अध्याय - 'पहली अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा' रोचक तो है ही, पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले को एयरपोर्ट और वहां होने वाली तमाम प्रक्रियाओं की भरपूर जानकारी भी देता है। अकेले यात्रा करना आपको कितना आत्मनिर्भर बना देता है, ये इस अध्याय को पढ़ के अन्दाज़ा हो ही जाता है। हवाई जहाज के अन्दर होने वाली छोटी-छोटी घटनाएं खूब विस्तार से लिखी हैं कविता ने वो भी बेहद रोचक तरीके से।

यूँ तो कविता वर्मा का आना हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार जब कविता मार्च में सतना आईं, एक विवाह समारोह के सिलसिले में, तो तीन मार्च को हमसे मिलने घर आईं और साथ में लाईं अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक 'अमेरिका जैसा मैंने देखा'। कविता के आने की खुशी अब दोगुनी हो गयी। यात्रा संस्मरण लिखना और पढ़ना दोनों ही हमारी रुचि में शामिल हैं और ये पुस्तक, कविता की अमरीका यात्रा पर केन्द्रित है सो मन में ज़्यादा उत्सुकता थी अमरीका को करीब से जानने की। पढ़ तो ली थी एक महीने पहले ही, लेकिन लिखने का मौक़ा अब लगा। उम्मीद है कविता माफ़ करेंगीं।

जैसा कि पुस्तक के नाम से ज़ाहिर है - 'अमरीका जैसा मैंने देखा' यह पुस्तक कविता की अमरीका यात्रा के शानदार संस्मरणों से भरी-पूरी है। पुस्तक में लगभग सभी संस्मरण, अमरीका के विभिन्न शहरों की संस्कृति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। पुस्तक के पहले अध्याय - 'पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा' रोचक तो है ही, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले को एयरपोर्ट और वहां होने वाली तमाम प्रक्रियाओं की भरपूर जानकारी भी देता है। अकेले यात्रा करना आपको कितना आत्मनिर्भर बना देता है, ये इस अध्याय को पढ़ के अन्दाज़ा हो ही जाता है। हवाई जहाज के अन्दर होने वाली छोटी-छोटी घटनाएं खूब विस्तार से लिखी हैं कविता ने वो भी बेहद रोचक तरीके से।

अगले अध्याय से अपने शहर न्यूजर्सी, यानी जहां कविता के बेटी-दामाद का निवास है, वहां से घूमने का सिलसिला शुरु हुआ। शहर की इमारतों, सड़कों और वहां की व्यवस्थाओं/नियमों का इतना शानदार, सजीव वर्णन कविता ने किया है कि लगता है जैसे हमने भी पूरा शहर घूम लिया हो। इमारतें कल्पना में ही साकार रूप लेने लगती हैं। हर व्यक्ति साफ़-सफ़ाई के प्रति कितना सचेत है! काश! हमारे यहां भी ऐसा

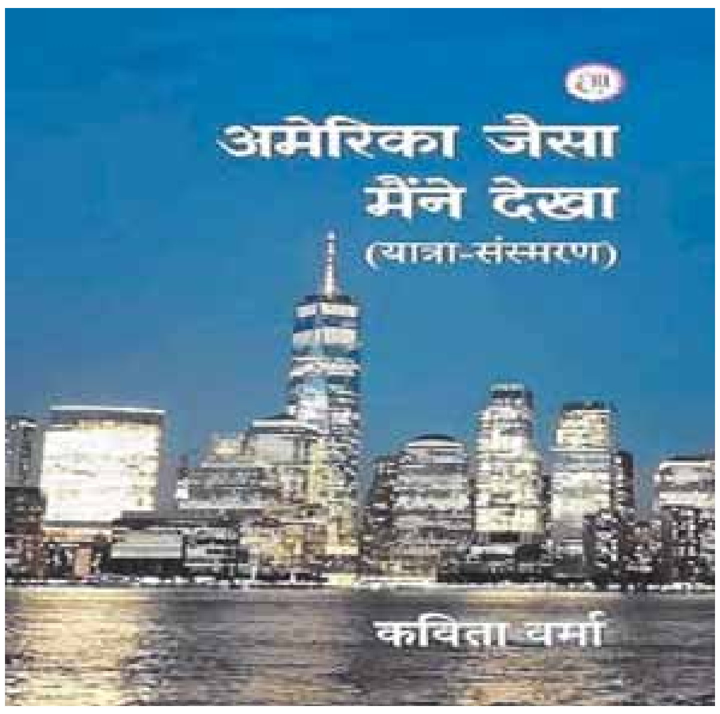

होता! सालोंसाल से सफ़ाई अभियान चल रहा यहां लेकिन स्थिति जस की तस! दोषी देश की जनता ही है जिसके भीतर अपनी ही गली-मोहल्ले को साफ़ रखने के संस्कार नहीं हैं। कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता का ईमानदार सहयोग उसमें शामिल न हो। कविता ने वहां काम के प्रति लोगों की ईमानदारी क बखूबी वर्णन किया है। सबसे मज़ेदार बात लगी - किसी से भी 'आई कॉन्टैक्ट' न करने वाली बात। वहां किसी को भी घूरना बहुत ग़लत माना जाता है। यहां तक कि वहां रह रहे भारतीय भी उन्हीं के रंग में रंग गये हैं। किसी अजनबी को भी देख के सहज मुस्कान यहां के लिये सामान्य बात है लेकिन वहां ये बात असभ्यता की निशानी मान ली जाती है।

वहां के यातायात नियमों को पढ़ के तो मज़ा ही आ गया। कितने सचेत हैं वहां के नागरिक अपने देश के नियमों के प्रति! अमरीका के छोटे-छोटे गांवों और जंगल के बीच बने केबिन में गुज़ारा गया एक दिन बेहद रोमांचक अध्याय है पुस्तक का। केबिन के अन्दर की सारी व्यवस्थाओं का तो कहना ही क्या! पुस्तक पढ़ के समझ में आता है कि कविता ने अमरीका को भरपूर जिया है।

माथे पर लगी बिन्दी के ज़रिये किसी पाकिस्तानी बुज़ुर्ग महिला से परिचय, बुज़ुर्ग सिक्ख दम्पत्ति से परिचय जैसी छोटी-छोटी घटनाएं भी विदेशी धरती पर कितनी बड़ी हो जाती हैं, ये कविता के अनुभव से जाना। कविता आगे न्यायार्क टाइम्स स्केवयर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ह्यूस्टन के फ़ार्मर्स मार्केट, ग्रेफ़िटी पार्क, वाटर वॉल, बीच हाउस जैसी जगहों का बेहद रोचक वर्णन करते हुए पाठकों को अपने साथ अमरीका यात्रा कराने में सफल रही हैं। ह्यूस्टन से वापसी का वृतान्त भी बहुत रोचक है।

कविता ने पूरा यात्रा संस्मरण इतने रोचक अन्दाज़ में लिखा है कि पाठक पढ़ते हुए एक पन्ना भी छोड़ नहीं सकता। कुल 165 पृष्ठ की यह पुस्तक अन्त तक बांधे रखती है। इतने विस्तार से किसी देश के बारे में लिखने के लिए कविता का दिल से शुक्रिया।

'अमरीका जैसा मैंने देखा' को कविता ने अपनी बिटिया कृति, दामाद नागा वीरेन्द्र ग्रन्थि और पतिदेव श्यामस्वरूप जी को समर्पित की है। 165 पृष्ठ की पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं। अद्विक पब्लिकेशन-दिल्ली से प्रकाशित इस पुस्तक की प्रिंटिंग बहुत शानदार है। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है, जो पुस्तक की सामग्री को देखते हुए एकदम वाजिब है।

शासकीय सेवकों की समग्र आईडी आधार से लिंक अनिवार्य

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन शासकीय सेवकों की समग्र आईडी का आधार से लिंक एवं सत्यापन शेष है, उसे शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए अन्यथा जुलाई वेतन रोका जाएगा। आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि आईएफएमआईएस प्रणाली में समग्र आईडी की आधार से मैपिंग का कार्य तत्काल पूरा होना चाहिए। निर्देशों के अनुसार, यदि किसी शासकीय सेवक की समग्र आईडी का ई - केवायसी -पूर्ण नहीं हुआ है तो ऐसे कर्मचारियों का जुलाई 2025 का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। केवल ई- केवायसी पूर्ण किए गए कर्मचारियों का वेतन जारी होगा।

केसूर में उप तहसील (टप्पा) कार्यालय

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आम जनता की सुविधाओं एवं राजस्व प्रशासन की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत केसूर तहसील धार को उप तहसील (टप्पा) कार्यालय सृजित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत क्षेत्रीय आवश्यकता, संसाधना व उपलब्ध स्टॉफ का उपयोग करते हुए धार जिले की तहसील धार की सीमाएं उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल केसूर के नवीन पटवारी हल्का नंबर 329 लगायत 348 तक को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित किया जाता है और राजस्व निरीक्षण मण्डल केसूर तहसील धार के नवीन पटवारी हल्का नंबर 329 लगायत 348 तक कुल 20 पटवारी हल्कों के 45 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए अन्य आदेश होने तक ग्राम पंचायत केसूर तहसील धार को उप तहसील (टप्पा) कार्यालय सृजित किया गया है।

डाक विभाग के लिए आईटी एप्लिकेशन का रोलआउट एक डिजिटल परिवर्तन की पहल साबित होग

धार। 21 जुलाई को डाक घर मे प्लान्ड डाउनटाइम अवकाश रहेगा। डाक विभाग अगली पीढ़ी के एपीटी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन के रोलआउट की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है, जो डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के सफर में एक बड़ा कदम है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत उन्नत प्रणाली को इंदौर मोफसिल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले धार, देवास, इंदौर के सभी डाकघरों में 22 जुलाई से लागू किया जाएगा। पोस्ट मास्टर धार कुणाल मकवाना ने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित परिवर्तन करने के लिए 21 जुलाई को एक नियोजित अवकाश प्लान्ड डाउनटाइम निर्धारित किया गया है। जिसमें इंदौर मोफसिल संभाग के सभी डाकघरों में कोई भी ग्राहक संबंधित लेन-देन नहीं किया जाएगा डेटा माइग्रेशन सिस्टम सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सेवाओं को अस्थायी रूप से 21 जुलाई को स्थगित किया जाना आवश्यक है, ताकि नई प्रणाली का संचालन सहज व कुशलतापूर्वक हो सके। डाक विभाग द्वारा डाक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एपीटी एप्लिकेशन को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, जो स्मार्ट, कुशल और भविष्य-उन्मुख डाक सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पोस्ट मास्टर मकवाना ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि 21 जुलाई को नियोजित अवकाश को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ के लिए पहले से योजना बनाकर निपटान किये जाये। साथ ही इस छोटे से अवकाश के दौरान सहयोग अपेक्षित है। डाक विभाग ने आश्वस्त किया है कि यह कदम बेहतर तेज और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं।

आरपीएफ जवान ने बचाई एक बुजुर्ग यात्री की जान

बैतूल। चलती ट्रेन पकड़ने के प्रयास में नीचे गिर गए एक बुजुर्ग यात्री की स्टेशन पर तैनात प्रधान आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को तुरंत ऊपर खींचकर जान बचाई। इस दौरान प्रधान आरक्षक भी यात्री को बचाने के प्रयास में नीचे गिर गया था। आरपीएफ बैतूल थाना प्रभारी राजेश बनकर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम को स्टेशन पर ट्रेन नंबर 12804 हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो रही थी। यहां ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश राजुरकर ने यात्रियों को सजग करने के लिए सिटी बजाकर टॉर्च जलाई। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री चलती ट्रेन का हैंडल पकड़ने के प्रयास में नीचे गिरने पर प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश राजूरकर ने तत्परता के साथ सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्री को तुरंत खींचकर गिरकर उसकी जान बचाई। इस दौरान प्रधान आरक्षक भी असंतुलन बिगड़ जाने से गिर गया था। यात्री को आरपीएफ ऑफिस में लाकर पूछताछ करने पर यात्री ने अपना नाम राकेश कुमार पिता कोमलचंद जैन (66) निवासी दयाराम उस्ताद अखाड़ा, 140 तेलीपुरा मस्कासाथ नागपुर महाराष्ट्र बताया। यात्री का आरक्षण स्लीपर कोच एस 5 में बर्थ नंबर 17 पर था। यात्री ने बताया कि वह भोपाल से नागपुर की यात्रा कर रहा था। ट्रेन बैतूल स्टेशन पर समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाने से वह ट्रेन से उतरकर बाहर बैठकर मोबाइल में कोई मैसेज आने पर उसे देखने लगा। उसे पता ही नही चला कि ट्रेन कब धीरे धीरे स्टेशन छोडने लगी थी। उसने दौडकर ट्रेन पकडने का प्रयास किया,लेकिन उसका हाथ छूट जाने से वह नीचे गिर गया। इसी बीच आरपीएफ के प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश राजुरकर ने तत्काल सहायता के लिए आकर पकडकर ऊपर खींचकर उसकी जान बचाई। यात्री ने गिरने से कोई चोट नहीं लगने की जानकारी दी।आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने बताया कि आरपीएफ का उद्देश्य ही है कि रेलवे की सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की जानमाल की रक्षा करना और आरपीएफ इस मामले में सजग और सतर्क है।

जनसामान्य को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने में परेशानी न हो : प्रभारी मंत्री

● विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से समय पर पूर्ण कराएं ● प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भैंसदेही में की विकास कार्यों की समीक्षा

बैतूल। जनसामान्य को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने में परेशानी न हो। सभी विभागीय अधिकारी अपनी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को और विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से समय पर पूर्ण कराएं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराएं। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं और मुद्दों का पूरी गंभीरता और तत्परता से समाधान किया जाएं। यह निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने शुक्रवार को जिले के भैंसदेही जनपद कार्यालय में आयोजित विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

विधानसभा स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के क्रम में शुक्रवार को प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भैंसदेही विधानसभा अंतर्गत भैंसदेही, भीमपुर और आठनेर ब्लॉक में योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुद्दों की जानकारी भी ली। बैठक में विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष भैंसदेही, राजा ठाकुर, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन सहित सभी जिला अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहें।

पटवारी अपने इलाकों पर रहे उपलब्ध ..राजस्व विभाग की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने सीमांकन और नक्शा दुरुस्ती के लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी अपने इलाकों पर निर्धारित दिवसों पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें और इनकी लोकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने पीएम आवास के शेष लक्ष्य को भी शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश तीनों जनपदों के जनपद सीईओ को दिए। उन्होंने कुकरु में आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर जनपद सीईओ भीमपुर को विशेष ध्यान के लिए निर्देशित किया।

पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करे ..प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि अभियान, अमृत 2.0, पीएम आवास योजना शहरी इत्यादि योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों को धारणाधिकार योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में भैंसदेही को 5 कॉलोनियों में मूलभूत विकास नहीं होने की समस्या पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैंसदेही को इन कालोनियों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही कर विकास किए जाने के निर्देश दिए।

आंगनवाड़ियों की मरम्मत के दिये निर्देश ...प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर निर्देशित किया कि स्वास्थ्य मूलक समस्त योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराएं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी मरीजों को निशुल्क इलाज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के भी प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने झल्लार में चिकित्सकों को कमी की समस्या पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सकों का युक्तियुक्तकरण कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सिकलसेल एनीमिया के प्रति स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। जर्जर आंगनवाड़ी भवनों संबंधी समस्या पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी को इन आंगनवाडि़यों के मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत आंगनवाडि़यों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदार पर करे कार्यवाही ...प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान झल्लार के बमहनवाडा में नल जल योजना का गुणवत्ताविहीन काम की शिकायत पर उन्होंने कार्यपालन यंत्री पीएचई को जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रगतिरत नल जल योजनाओं के काम गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने पी एच ई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कहा कि नल जल योजनाओं और डेम निर्माण कार्यों में लापरवाही न हो।

विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं का त्वरित करे निराकरण ..

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा कर मृदा स्वास्थ्य मिशन का व्यापक प्रचार प्रसार करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण कराने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन संबंधी कार्यों से स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोडने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने महाप्रबंधक एमपीईबी को नवीन उपकेंद्रों के निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने और विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केंद्रों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जाएं। लोक सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जाएं और केंद्र के कर्मचारी आमजन के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। निर्धारित राशि से अधिक लेने वाले लोक सेवा केंद्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएं। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने खनिज, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि विभागों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर 100 फीसदी उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए।

दक्षिण वनमंडल ने अब तक रोपे 7.25 लाख पौधे

बैतूल। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दक्षिण वनमंडल ने इस वर्ष वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ ही एक प्रभावी पहल की है। डीएफओ विजयानन्तम टी.आर. के मार्गदर्शन में दक्षिण बैतूल वनमंडल अंतर्गत समस्त परिक्षेत्रों में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में स्कूली छात्र-छात्राएं, शिक्षक, आम नागरिक, वन समिति सदस्य, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। 18 जुलाई 2025 तक वनमंडल अंतर्गत कुल 7,25,306 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। यह जानकारी भारत सरकार के मेरी लाइफ वेब पोर्टल पर भी दर्ज की गई है। इसी क्रम में 18 जुलाई को प्रभारी मंत्री, नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन एवं महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक, भैंसदेही द्वारा ईको टूरिज्म केंद्र, कुकरू के प्रवास के दौरान परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपवनमंडलाधिकारी भैंसदेही देवानंद पाण्डेय, परिक्षेत्र अधिकारी भैंसदेही जी.एस. नरगेश, वन कर्मचारी एवं अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

956 फोटो वायुदूत एप पर अपलोड-अब तक वनमंडल अंतर्गत 42 विद्यालयों में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं, अध्यापकों और वन कर्मचारियों द्वारा मिश्रित प्रजातियों के 4665 पौधे रोपे जा चुके हैं। इन पौधों में आम, सीताफल, आंवला, पीपल, करंज और अनार जैसे फलदार व औषधीय प्रजातियां प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इस अभियान में वन कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वायुदूत एप पर पौधारोपण की फोटो अपलोड करने का लक्ष्य भी तय किया है। इस दिशा में वनमंडल के कर्मचारियों द्वारा अब तक कुल 1546 पौधे रोपित कर 956 फोटो वायुदूत एप पर अपलोड किए जा चुके हैं।

क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कांधे पर उठाई कावड़

बैतूल/मुलताई। सालबर्डी में 21 जुलाई को होगा ताप्ती जल से भोलेनाथ का अभिषेक। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पवित्र नगरी मुलताई में प्रथम आगमन पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर वासियों ने भव्य स्वागत किया। सर्व मंगल कावड़ यात्रा में भाग लेने मुलताई पहुंचे हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि ताप्ती तट से निकलने वाली सर्व मंगल कावड़ यात्रा में वह प्रतिवर्ष आते रहे हैं, इसलिए इस वर्ष भी आए हैं। यह कावड़ यात्रा के प्रतिफल में क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर हेमंत खंडेलवाल का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डीडी उईके, मोहन नागर, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, जिला भाजपा अध्यक्ष सुधाकर पवार भी उपस्थित थे। खंडेलवाल के स्वागत का सिलसिला परमंडल जोड़ से प्रारंभ हो गया था। इसके बाद ताप्ती तट पहुंचने तक एक दर्जन से भी अधिक स्थानों पर उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और हेमंत खंडेलवाल भी गाड़ी से उतरकर प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलते दिखाई दिए। इसके बाद हेमंत खंडेलवाल ताप्ती मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां ताप्ती की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत राम मंदिर से प्रारंभ हुई कावड़ यात्रा में शामिल होकर कावड़ यात्रा के साथ ताप्ती सरोवर परिक्रमा की। कंधे पर ताप्ती जल से भरी कावड़ लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए ताप्ती तट से शिवधाम सालबर्डी के लिए रवाना हुए।

मैं कहीं भी पहुंच जाऊं बैतूल के लिए हमेशा सामान्य कार्यकर्ता ही रहूंगा : हेमंत खंडेलवाल

● मेरे दिल के कैमरे आप हमेशा रहोगे : प्रदेश अध्यक्ष

बैतूल। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने जिला पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। भाजपा जिला कार्यालय विजय भवन में शुक्रवार को आयोजित भाजपा की जिला बैठक को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मैं भले ही आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ लेकिन बैतूल के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उन्होने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा बैतूल का तीसरा प्रवास है। जब मैं प्रथम बार आया था तो बैतूल की जनता का अपार प्यार मिला उसकी नींव में आप थें। दूसरी बार आया तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी मैंने उस दिन सभी गुरुओं का आर्शीवाद प्राप्त किया। आज जब तीसरी बार आपके बीच आया, तो सबसे पहले माँ ताप्ती को नमन करके आपके बीच आया हूँ।

श्री खंडेलवाल ने कहा कि मॉ ताप्ती जिनके कारण किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। जिसके आर्शीवाद से हमे धन्य धान्य एवं यश की प्राप्ती होती है। ऐसी ताप्ती मॉ को सबसे पहले नमन करके इस बैठक में आया हूॅ। इसके पूर्व बैठक का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, जनअभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर सहित सभी अतिथियों ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी , पं. दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के छायाचित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित दल है। यह पार्टी न किसी परिवार के बल पर चलती है और न ही किसी जाति के आधार पर। भाजपा कार्यकर्ताओ के परिश्रम और पार्टी के प्रति उनके अथाह परिश्रम के भाव से संचालित होती है। सभी कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करें। सभी जन प्रतिनिधि जिला पदाधिकारियों के साथ बैठकर जिले के विकास एवं संगठन के विस्तार की रणनीति बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी कारण से मेरी फोटो न आ पाई हो, लेकिन मेरे दिल के कैमरे में आप हमेशा के लिए कैद रहेगें। हम सब एक मत होकर राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के लिए काम करें।

जो विधानसभा कम अंतर से जीते है या जो वार्ड हम नहीं जीत पाए है। वहां पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सब मिलकर काम करें। जो थोड़ी बहूत कमी है उसे आपस मे मिल बैठकर दूर करें। कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कोई कमी नही रहें। हर महिने जिले की बैठक हो उसके बाद मंडल और शक्तिकेन्द्र की बैठके संपन्न हो। हर तीन महीने में पदाधिकारियों के परिवार का मिलन हो। सभी विधायक सप्ताह में एक दिन जिला कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सूने। बैठक को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी पंकज जोशी ने कहा कि बूथ समिति और मंडल समिति के सभी कार्यकर्ताओ का डेटा संगठन एप्प में अनिवार्य रूप से अपलोड करें। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन शत प्रतिशत बूथों पर करने हेतु योजना बनाए। शक्ति केन्द्रों का पुनर्गठन कर सभी बूथों को सक्रिय करें। जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि जिला पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओ को प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिल रहा है।

प्रदेश द्वारा जो भी कार्यक्रम मिलेगा बैतूल के सभी कार्यकर्ता उसे शत प्रतिशत सफल बनाएगें। बैठक को जिला प्रभारी सुजीत जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, आमला विधायक डा.योगेश पंडाग्रे, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अलकेश आर्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने किया एवं अंत में आभार प्रदर्शन जिला कार्यालय मंत्री कृष्णा गायकी ने व्यक्त किया।

शाहपुर में वैश्य महासम्मेलन एवं आजीवन सदस्यों का सम्मेलन आगामी 27 को

● समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का होगा अभिनंदन एवं सम्मान

बैतूल। वैश्य महासम्मेलन इकाई बैतूल के तत्वावधान में आगामी 27 जुलाई को शाहपुर में जिला कार्यकारिणी की बैठक एवं आजीवन सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला इकाई बैतूल की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का अभिनंदन एवं सम्मान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री राजीव खंडेलवाल के नेतृत्व में पदाधिकारीगण एवं वैश्य बंधु उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया। माननीय हेमंत खंडेलवाल ने सहर्ष स्वीकार कर कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की है। उक्त कार्यक्रम में उमाशंकर गुप्ता, संरक्षक, सुधीर अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, वैश्य महासम्मेलन म.प्र. विशेष रूप से मार्गदर्शन देने हेतु उपस्थित रहेगें। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश कार्यकारणी सदस्य बिरदीचंद पगारिया, जिलाध्यक्ष अखिलेश गोठी, जिला महामंत्री हेमंत पगारिया, अनिल बांगड, जिला उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, राजकुमार (राजु) अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, किशोर (डब्बू) जैन, मनीष (बंटी) खंडेलवाल, ब्रजकिशोर खंडेलवाल, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य तपन मोनू खंडेलवाल, देवेन्द्र (जैन) घोपाडे, मुलताई, अधिवक्ता आलोक गोयल, हरदा आदि मौजूद रहे।

नवजात शिशुओं की माताओं को छुट्टी से पहले मिला जन्म प्रमाण पत्र

बैतूल। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंशानुरूप जिले में नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र उनकी माताओं को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जनपद भैंसदेही के शासकीय अस्पताल पहुंचकर तीन माताओं को उनके नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र सौंपा।

शासन की मंशा के अनुरूप माता श्रीमती फूलवंती, श्रीमती रितु वाड़िवा, श्रीमती गंगा को छुट्टी से पूर्व ही उनके बच्चे का पहला कानूनी दस्तावेज सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाड़े तथा स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि स्वास्थ्य मूलक योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी भी दी।

जिला न्यायालय में प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थों के साथ बैठक का आयोजन

बैतूल। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत जिला न्यायालय बैतूल में 18 जुलाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवबालक साहू, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती शर्मिला बिलवार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय एवं जिले के प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थ बीके पांडे, देवधन चढ़ोकार, संजय चौरसे, अजय सिंह चौहान, रघुनाथ निरापुरे, राकेश कुमार सोनारे, संदीप कुमार खाण्डवे, श्रीमती गीता पंवार, श्रीमती सुनंदा नागले, लवकुश निरापुरे एवं नरेन्द्र चौरसिया उपस्थित रहे।

बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पूरे भारत में 1 जुलाई 2025 को 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान लागू किया गया है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। उक्त अभियान अंतर्गत जिला बैतूल एवं अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में लंबित दुर्घटना दावा, घरेलु हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सर्विस मेटर, आपराधिक शमनीय प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, वटवार, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य सिविल प्रकरणों का मध्यस्थ के माध्यम से निराकरण कराया जाना है।

संक्षिप्त समाचार

जिला पंचायत सीईओ ने की शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने जिले की शैक्षणिक गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी बीआरसीसी, बीएसी एवं जन शिक्षकों से शालाओं में शत-प्रतिशत छात्र नामांकन, मध्यान्ह भोजन, पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, स्कूलों में साफ-सफाई, मरम्मत एवं अध्यापन कार्य के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रोफाइल अपडेशन, यू डाइस पोर्टल एन्ट्री, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत असाक्षरो का शत-प्रतिशत सर्वे करने एवं अक्षर साथी पंजीयन तथा मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि विकासखण्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएसी जन शिक्षकों को सम्मानित किये जाए और कार्य में लापरवाही बरतने वाले एवं कार्य पूरा नही करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला परियोजना समन्वयक श्री आरआर उइके, सहित सहायक परियोजना समन्वयक, सभी विकास खंडों के बीआरसीसी, बीएसी एवं जन शिक्षक उपस्थित थे।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया पौधा रोपण

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज हुरमाड़े ने सोमवार को पुराना एएनएमटीसी बैतूल में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। सीचएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने कहा कि वास्तव में पर्यावरण संतुलन के लिये सबसे ज्यादा आवश्यक पौधा रोपण है। यदि प्रत्येक कर्मचारी पौधा रोपण का संकल्प ले तो यह कदम प्राकृतिक संतुलन के लिये बहुत प्रभावी होगा। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश परिहार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ प्रांजल उपाध्याय एवं एएनएम द्वारा भी पौधा रोपण किया गया।

निरीक्षण कर जायजा लिया

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बुधवार को कुरवाई प्रवास के दौरान नवनिर्मित एसडीएम तहसील कार्यालय भवन का जायजा लिया और कक्षो के अन्दर गुणवत्ता को परखा है इसी प्रकार कुरवाई के सांदीपनी स्कूल के निर्माण कार्यो का भी अवलोकन कलेक्टर द्वारा किया गया है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने सांदीपनी स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री जी के प्रवास को ध्यानगत रखते हुए आने जाने के व्हीआईपी मार्ग का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। परिसर में संचालित शासकीय बालक छात्रावास में पहुंचकर छात्रावासी बच्चों से संवाद किया और जानकारियां प्राप्त की है। कलेक्टर श्री गुप्ता को कक्षा सातवीं के नीलेश और कक्षा नौवी के सौरभ ने संवाद के दौरान प्रश्नोत्तरी जानकारियां दी है। छात्रावास अधीक्षक को निर्देश दिए गए है कि संधारित लायब्रेरी में दैनिक समाचार पत्रो की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए ताकि छात्रावासी बच्चे सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में अपडेट रहें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया, एसडीएम श्री नितिन कुमार जैन के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी खण्ड स्तरीय अधिकारी साथ मौजूद रहें।

जिले के समस्त सीएचओ का कफ अगेस्ट टीबी एआईस्क्रीनिंग टूल के उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षण आयोजित

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सभाकक्ष में बुधवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिले के समस्त सीएचओ का कफ अगेस्ट टीबी एआईस्क्रीनिंग टूल के उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार हुरमाड़े ने सीएचओ को प्रशिक्षण में बताया कि सभी लोग नए एप का उपयोग कर संभावित टीबी मरीजों की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग करें, ताकि हम जिले को टीबी मुक्त कर सकें। राज्य सलाहकार टीबी डॉ प्रज्ञा दुबे ने बताया कि टीबी के खिलाफ खांसी एप्लीकेशन एक एआई संचालित खांसी ध्वनि आधारित स्क्रीनिंग समाधान है।इस एप से शीघ्र ही खांसी के नमूने के विशलेषण के आधार पर व्यक्ति में टीबी होने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ तथा सभी एसडीएम ने शासकीय स्कूलों का किया निरीक्षण

शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों और मध्यान्ह भोजन का लिया जायजा

शाला से अनुपस्थित मिले शिक्षक-शिक्षिका को नोटिस जारी

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को जिले में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर शैक्षणिक कार्य तथा मध्यान्ह भोजन का जायजा लिया गया। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला सेहतगंज और शासकीय प्राथमिक शाला गौपीसुर सतकुण्डा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों और बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ द्वारा बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई गई तथा प्रश्न भी पूछे गए। साथ ही शाला में स्थित रसोई का भी निरीक्षण किया और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता देखी। इसी प्रकार रायसेन एसडीएम श्री मुकेश सिंह द्वारा एकीकृत शासकीय शाला बरूखार तथा एकीकृत शासकीय शाला पैमत का निरीक्षण किया गया। बरेली एसडीएम श्री संतोष मुद्गल द्वारा शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बरेली तथा बेगमगंज एसडीएम श्री सौरभ मिश्रा द्वारा शासकीय सांदीपनी विद्यालय बेगमगंज, शासकीय प्राथमिक शाला बारिकलॉ, शासकीय माध्यमिक शाला उमरखोह तथा शासकीय हाईस्कूल उमरखोह का निरीक्षण किया गया। गौहरगंज, सिलवानी और गैरतगंज क्षेत्र में भी एसडीएम द्वारा शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया गया। शासकीय स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों, प्रवेशित बच्चों की संख्या, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित होने तथा मध्यान्ह भोजन वितरण की जानकारी ली गई। साथ ही बच्चों से भी संवाद कर विद्यालय समय पर खुलने, शिक्षकों के नियमित आने, मध्यान्ह भोजन गुणवत्तापूर्ण मिलने संबंधी जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी

जिला पंचायत सीईओ द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला सेहतगंज के निरीक्षण किए जाने के दौरान माध्यमिक शिक्षक जरीन फातमा तथा शासकीय प्राथमिक शाला गोपीसुर सतकुण्डा के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक सौरब कुमार चौरसिया बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से शाला से अनुपस्थित पाए गए। संबंधित शिक्षकों को शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अनियमितता बरतने और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त नहीं होने या समाधानकारक नहीं होने पर संबंधित शिक्षक-शिक्षिका के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शासकीय हाईस्कूल का किया आकस्मिक निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा बुधवार को रायसेन में वार्ड क्रमांक-04 कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्थित शासकीय हाईस्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। साथ ही शिक्षकों से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित होने, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से भी संवाद कर विद्यालय नियमित खुलने, शिक्षकों की उपस्थिति और अध्यापन कार्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछकर उनका शैक्षणिक स्तर भी परखा। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सभी विद्यार्थी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें।

रोगी कल्याण समिति की बैठक सम्पन्नः मरीजों को सुविधाओं के विस्तार के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नर्मदापुरम (निप्र)। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में रोगी कल्याण समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कार्यवाहियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक नर्मदापुरम डॉ. सीतासरन शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष नर्मदापुरम श्री भूपेंद्र चौकसे, डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौड़, सिविल सर्जन डॉ. सुनीता कामले, सीएमएचओ श्री नरसिंह गहलोत, श्री अर्पित मालवीय, श्री अनुराग तिवारी सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा वर्ष 2024-25 के रोगी कल्याण समिति के आय व्यय के विवरण पर चर्चा की गई। इसके पश्चात प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा कर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति सदस्यों द्वारा चिकित्सालय में 30 नए कूलर एवं पंखे की व्यवस्था किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर के रास्ते को ठीक करवाए जाने के लिए भी समिति सदस्यों द्वारा एक मत सहमति दी गई। रोगी कल्याण समिति की बैठक के दौरान जिला चिकित्सालय परिसर में नाली निर्माण कार्य के संबंध में सिविल सर्जन द्वारा जानकारी दी गई की नली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला चिकित्सालय में शीघ्र ही डायलिसिस सुविधा के लिए डायलिसिस को जनरेटर से कनेक्शन किए जाने की भी सहमति समिति सदस्यों द्वारा दी गई। इस दौरान विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा ने कहा कि मोर्चरी कक्षा की मरम्मत एवं डीप फ्रीजर तथा वाटर कूलर एवं परिजनों के बैठने की सुविधा के लिए शेड निर्माण एवं बेंच की व्यवस्था किए जाने के लिए उचित कोटेशन प्राप्त कर तथा भंडार क्रय नियम अनुसार खरीदी की जाए।

कलेक्टर विश्वकर्मा ने अधिकारियों को दिए मूंग उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश

स्कूलों का भी सतत् निरीक्षण कर शैक्षणिक कार्य और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता जांचने के निर्देश

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन, उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण, सीएम हेल्पलाईन, स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन वितरण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल समय पर खुलें और शिक्षक निर्धारित समय पर स्कूलों में उपस्थित रहे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन वितरण की भी जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मीनू अनुसार ही मध्यान्ह भोजन मिले। कहीं से भी निम्न गुणवत्ता के मध्यान्ह भोजन वितरण की शिकायत प्राप्त ना हो। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण की भी जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि स्कूलों का निरीक्षण कर देखें कि सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितररित हो गई हैं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि मूंग उपार्जन केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करें तथा शासन की उपार्जन नीति अनुसार मूंग उपार्जन कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने सभी एसडीएम को भी अपने क्षेत्रों में मूंग उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार आवारा या निराश्रित गौवंश सड़कों पर ना रहे, इसके लिए एसडीएम, जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अधिकारी सतत् भ्रमण करें। साथ ही आवारा या निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में छुड़वाया जाए। जिन पशुपालकों द्वारा अपने गौवंश को सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, उन्हें समझाईश दें और इसके उपरांत भी नहीं मानने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और किसानों को वितरण की भी जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का स्टॉक रहे। किसानों को गुणवत्तापूर्णक उर्वरक ही मिले, यह भी सुनिश्चित कराएं। इसके लिए निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें तथा उर्वरकों के सैम्पल लिए जाएं। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में उर्वरकों की नियमित आपूर्ति हो रही है। अभी जिले में 3000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा गुरूवार तक दो हजार मीट्रिक टन यूरिया जिले को प्राप्त होगा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि जिले में कहीं से भी उर्वरक वितरण में अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत समाधान कराएं। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने गंभीरतापूर्वक समयावधि में सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने भी अधिकारियों को स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार सहित डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, उप संचालक कृषि, डीपीसी सहित अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जेएच कॉलेज के विज्ञान भवन में बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बैतूल (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बैतूल श्री मकसूद अहमद के नेतृत्व में बैतूल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-131 अंतर्गत बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को जेएच कॉलेज के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 100 तक के बीएलओ के लिए प्रथम एवं द्वितीय बेंच के अंतर्गत आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री दिलीप कुमार दाबड़े एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री नागेश पवार, श्री धनराज सूर्यवंशी, श्री हीरेंद्र शुक्ला, श्री धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, श्री पुरुषोत्तम सोनकुसले, श्री कमलेश लिल्होरे, श्री चंद्र हुरमाड़े, श्री अभय जोशी द्वारा बीएलओ को निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, नायाब तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री श्याम उइके, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री रोमित उईके की उपस्थिति रही।

बीएलओ को निर्वाचन कार्य से संबंधित जानकारी से अवगत : अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव ने सभी बीएलओ को मतदाता सूची शुद्धीकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रहे एवं अपात्र मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है, स्थानांतरण हो गया है, ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बैतूल द्वारा बीएलओ के कर्तव्य, संविधान की धाराएं एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा बीएलओ को निर्वाचक नामावली के त्रुटिरहित बनाने के निर्देशों में निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी प्रक्रिया, घर-घर जाकर सर्वे कर निर्वाचक की जानकारी का सत्यापन करना, मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि की जानकारी तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, बूथ लेवल एजेन्ट से समन्वय, फार्म-6, 7 व 8 एवं बीएलओ एप्ष आदि के संबंध में बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण में प्रातः 10 बजे से पंजीयन कार्य, किट वितरण किया गया। प्रथम चरण में बीएलओ को संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। द्वितीय चरण में बीएलओ की जिम्मेदारियां, रोल-प्ले, बीएलओ ऐप, वीएचए ऐप तथा फार्म-6, 6ए, 7, 8 भरने का अभ्यास कराया गया।

जल जीवन मिशन के एक नल कनेक्शन ने बदल दी मनीषा की दुनिया

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले के भैरूंदा तहसील की ग्राम पंचायत खड़गाँव निवासी श्रीमती मनीषा यदुवंशी का जीवन कभी कठिन संघर्षों से भरा हुआ था। मात्र 45 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा जीवन देखा है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। करीब 20 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके पति का निधन हो गया। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। इससे पहले कि मनीषा इस दुख से उबर पातीं उसी समय उनके इकलौते बेटे ने भी गंभीर बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया। अब मनीषा और उनकी बेटी ही एक-दूसरे का सहारा रह गए थे। अत्यधिक गरीबी, मानसिक आघात और जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर था। उन्हें रोज़ सुबह मीलों दूर से पानी लाना पड़ता, घर के सारे काम निपटाकर बेटी को स्कूल भेजना और फिर मजदूरी की तलाश में निकलना पड़ता था। कभी-कभी समय पर घर का काम समय पर पूरा न होने के कारण मजदूरी भी हाथ से निकल जाती थी।

फिर मनीषा के जीवन में बदलाव आया और उनके गांव के साथ ही उन्हें जल जीवन मिशन की सौगात मिली। जीवन की इस कठिन डगर पर चलते हुए एक दिन उम्मीद की किरण मनीषा के गांव में पहुंची। जल जीवन मिशन के तहत नीलकंठ-भैरूंदा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत उनके घर में भी नल कनेक्शन लग गया। यह सिर्फ एक नल नहीं था, बल्कि मनीषा के लिए यह राहत, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत थी। नल कनेक्शन मिलने से अब उन्हें रोज़ दूर पानी लाने नहीं जाना पड़ता। स्वच्छ पेयजल घर पर ही समय पर उपलब्ध हो जाता है। इससे न केवल उनका समय बचता है, बल्कि वे अपनी बेटी की देखभाल और घरेलू कार्य भी अच्छे से कर पाती हैं। जल जीवन मिशन ने श्रीमती मनीषा को सिर्फ पानी नहीं दिया, एक नई पहचान भी दी। गांव की ग्राम पंचायत ने उन्हें जलकर संग्रहण का कार्य सौंपा। अब वे घर-घर जाकर जलकर एकत्र करती हैं, जिसके बदले उन्हें कुल संग्रह राशि का 15 प्रतिशत मेहनताना मिलता है। इस आय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब वे न सिर्फ अपनी बेटी की शिक्षा को सुचारु रूप से चला पा रही हैं, बल्कि परिवार की आवश्यकताएं भी पूरे आत्मसम्मान के साथ पूरी कर रही हैं।

मनीषा यदुवंशी की कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएं जब ज़मीन तक सही तरीके से पहुंचती हैं, तो वे किसी का जीवन बदल सकती हैं। जल जीवन मिशन न केवल गांवों को जल सुविधा दे रहा है, बल्कि महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। श्रीमती मनीषा आज सिर्फ एक लाभार्थी नहीं हैं, वे अब गांव में महिलाओं के लिए प्रेरणा की जीवंत मिसाल बन चुकी हैं।

बाल अधिकारों के संबंध में किशोर एवं ग्रामीणजन को किया गया जागरूक

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत लगाये पौधे

हरदा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन में मंगलवार को ग्राम पंचायत मुहालकलां, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौकड़ी, ग्राम पंचायत पाहनपाट एवं ग्राम पंचायत नगावामाल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया तथा पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि बाल अधिकार जागरूकता अभियान का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल यौन शोषण बाल विवाह, बाल श्रम आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए है। शिविरों में बताया गया कि नालसा की ''साथी'' योजना बच्चों की कानूनी पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निराश्रित और वंचित बच्चों को कानूनी पहचान प्रदान करना, आधार पंजीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण तक पहुंच सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक पुनर्वास और समावेशन को सक्षम करना है। इस योजना के तहत निराश्रित, अनाथ और परित्यक्त बच्चों की पहचान की जाएगी तथा उनके आधार कार्ड बनवाए जाएंगे। इससे उन्हें न केवल एक पहचान मिलेगी, बल्कि वे समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे।

सीएम ने स्पेन में की निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग की नई पहल

कैटलोनिया के विदेश मंत्री जैम डच गुइलोट के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पेन यात्रा के तीसरे दिन बार्सिलोना में कैटलोनिया सरकार के विदेश मंत्री श्री जैम डच गुइलोट से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान आईआईटी इंदौर और आयसर भोपाल को बार्सिलोना के विश्वविद्यालयों से जोड़ते हुए अकादमिक और शोध सहयोग को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश विश्वस्तरीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कैटलोनिया की अग्रणी कंपनियों को मध्यप्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और युवा शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सही समय है जब यूरोपीय कंपनियाँ मध्यप्रदेश को अपने निवेश गंतव्य के रूप में देखें।

खेल, पर्यटन और संस्कृति में साझेदारी के नए आयाम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एफसी बार्सिलोना फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ मिलकर खेल, नेतृत्व और जीवन कौशल पर आधारित कार्यक्रमों की साझेदारी की संभावनाएं साझा कीं। साथ ही मध्यप्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों साँची, खजुराहो और भीमबेटका को यूरोप में प्रमोट करने के लिए संयुक्त पर्यटन अभियान पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों सरकारें प्रदर्शन कला, सिनेमा, साहित्य और संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद को और सशक्त बनाएं।

तकनीकी सहयोग और नीति–स्तरीय समन्वय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्मार्ट सिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स और शहरी परिवहन में कैटलोनिया की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए तकनीकी सहयोग प्रस्तावित किया। उन्होंने दोनों सरकारों के बीच एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की बात कही, जो प्रमुख परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश की सशक्त उपस्थिति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मुलाकात को प्रदेश की वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब निवेश, शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के लिए तैयार है, और स्पेन यात्रा प्रदेश के विकास में नए अध्याय जोड़ेगी।

तिघरा डैम के 7 गेट खोले, 20 गांवों में अलर्ट

छतरपुर में पानी में डूबा गांव, नदी में बही एंबुलेंस, शिवपुरी में आज स्कूल रहेंगे बंद

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। छतरपुर-टीकमगढ़ में कई गांव पानी में डूबे हैं। ग्वालियर में तिघरा डैम का जल स्तर 738.20 बढ़ने पर सात गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से पहले आसपास के 20 गांव में अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को ग्वालियर-चंबल के 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा पानी गिरा। खजुराहो में 6 इंच, नौगांव में 5.2 इंच बारिश हुई। सतना में 5.7 इंच, दतिया में 5.1 इंच, टीकमगढ़ में 3.6 इंच, गुना में 3 इंच, रीवा में 2.3 इंच, ग्वालियर में 1.8 इंच, पचमढ़ी में 1 इंच बारिश दर्ज की गई।

इंदौर-भोपाल में भी गिरेगा पानी– मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, राजगढ़, आगर-मालवा, सिवनी, नीमच, मंदसौर में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली के साथ मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है।

पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, अनूपपुर, जबलपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, सिंगरौली में भी हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। मऊगंज में कटरा मुख्य मार्ग का बड़ा हिस्सा बारिश के कारण बह गया। नई गढ़ी से मऊगंज आने-जाने के लिए देवतालाब का वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

छतरपुर में तेज बारिश में दो मकान ढहे, बेटी की मौत, माँ घायल– छतरपुर में तेज बारिश की वजह से अलग-अलग गांवों में दो मकान ढह गए। पहली घटना में बेटी की मौत हो गई, मां घायल है। दूसरी घटना में युवक की जान चली गई। नारायणपुरा रोड पर साइकिल से नाला पार करते वक्त युवक बह गया। पुलिस तलाश में जुटी है। शिवपुरी में बारिश के चलते आज नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। छतरपुर में रनगुवां डैम के 12, कुटनी के 7 और लहचूरा डैम के 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। शिवपुरी में मड़ीखेड़ा अटल सागर बांध के 2 गेट खोले गए हैं। छतरपुर में बमीठा झांसी फोरलेन पर एम्बुलेंस पानी में बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया। धामची गांव में उर्मिल नदी का पानी घुसने से 200 परिवार फंस गए थे। एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि टीमें भेजकर 15 लोगों को रेस्क्यू कराया है। टीकमगढ़ में पूनौल नाला उफान पर है। पुल के ऊपर से 3 फीट तक पानी बह रहा है। झांसी हाईवे पर ट्रैफिक बंद करा दिया गया है। छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, डिंडौरी और मऊगंज में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश रहा।

चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हूं : उमा भारती

राजनीति में शुचिता आई, अब अफसरशाही में आना जरूरी, तभी रुकेगा भ्रष्टाचार

भोपाल (नप्र)। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि राजनीति में अब शुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने यह बातें कही। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें 75 वर्ष की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात कही गई थी। उमा ने स्पष्ट किया कि उनकी उम्र अभी 75 वर्ष नहीं हुई है और इस बयान को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, वे पूरी तरह गलत और निराधार हैं।

चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं

उमा भारती ने कहा, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जैसे डॉक्टर, कलाकार, लेखक कभी रिटायर नहीं होते, वैसे ही राजनेता भी जनता की जरूरत पर खड़े होते हैं। आज भी जब पार्टी चाहेगी, मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगी।

सरकारी तंत्र से भी झेलनी पड़ी प्रताड़ना

उमा भारती ने कहा कि 1990 से 1992 के दौरान जिन सरकारों का दबाव था, उस समय उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में जब व्यापमं घोटाला उजागर हुआ था, तब भी उनका नाम घसीटा गया और उन्हें उस समय भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

उन्होंने कहा कि वह अब अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो रही हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय बनी रहेंगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि गंगा, गोमाता और शराबबंदी को लेकर उनका संघर्ष आजीवन जारी रहेगा।

शराबबंदी पर और प्रयास जरूरी

उमा ने कहा कि केंद्र सरकार गंगा शुद्धिकरण के लिए काम कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी गाय के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि, अभी इन दोनों क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

दाहोद में बने शक्तिशाली इंजन की भोपाल में ट्रायल

भोपाल में दौड़ेगा 9000 हॉर्स पॉवर का देसी इंजन, 26 कोच वाली ट्रेनें चलाएगा

भोपाल (नप्र)। रेलवे ने स्वदेशी निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दाहोद (गुजरात) में 9000 हॉर्सपावर क्षमता वाला भारत का सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक रेल इंजन तैयार किया है। यह इंजन जल्द ही भोपाल में ट्रायल पर दौड़ता नजर आएगा। यह 130 डिब्बों वाली भारी मालगाड़ी को अकेले खींचने में सक्षम है। वर्तमान में ऐसे काम के लिए दो इंजन (5500-5500 एचपी) की जरूरत पड़ती है।

इस इंजन की शक्ति और बहुउपयोगिता को देखते हुए इसे यात्री ट्रेनों में भी शामिल किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह गोवा, जीटी, तमिलनाडु, सचखंड, मंगला एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की 26 से 28 कोच वाली ट्रेनों को खींचने में सक्षम होगा। ये ट्रेनें भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरती हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंजन को दो महीने पहले राष्ट्र को समर्पित किया था।

15 दिन तक चलेगी ट्रायल प्रक्रिया– पश्चिम-मध्य रेलवे के तहत भोपाल, जबलपुर और कोटा रेल मंडलों को पहले चरण में तीन इंजन आवंटित किए जाएंगे। इन मंडलों के अधिकारी इसकी कार्यप्रणाली समझने और रूट फिटनेस जांचने के लिए ट्रायल चलाएंगे। भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि ट्रायल की प्रक्रिया करीब 15 दिन तक चलेगी। इसके बाद फाइनल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंत्रालय स्थित कक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा की।

सड़क के गड्‌ढों पर गरमाई राजनीति

पीसीसी चीफ बोले–सरकार को गड्‌ढों में डूब मरना चाहिए, मंत्री जल समाधि ले लें

भोपाल (नप्र)। सड़कों में हो रहे गड्‌ढों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सड़कों के निर्माण में करप्शन का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि गड्‌ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए या फिर स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए।

पटवारी ने प्रदेश के आईएएस-आईपीएस अफसरों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। पटवारी ने ये बातें गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहीं।

उन्होंने कहा कि एमपी में सड़कों की हालत सबके सामने है। लोगों का पैसा लूटने वाले मंत्री जवाबदेही स्वीकार करने के बजाय यह कह रहे हैं कि सड़कें हैं तो गड्‌ढे होते रहेंगे। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो लूट के काम में न लगा हो।

चहेती कंपनियों को टेंडर देने के नियम– पटवारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस का दो दिनी प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें एमपी सरकार के 52 घपलों पर चर्चा होगी और इसे विधानसभा में जोर-शोर से उठाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के लिए कराए जाने वाले कामों में करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि सिंहस्थ को लेकर एमपी में सरकार द्वारा ऐसे नार्म्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें चहेती कंपनियों को सीधा टेंडर देने की प्लानिंग की जा रही है। हैदराबाद और गुजरात की कंपिनयों को इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है।

कांग्रेस लाएगी रोजगार, करप्शन पर श्वेत पत्र– पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि वर्ष 2013 से आज तक कितने बच्चों को रोजगार दिया है। इसका मामला विधानसभा में उठाएंगे। कांग्रेस रोजगार और करप्शन को लेकर श्वेत पत्र लाएगी। सरकार से श्वेत पत्र मांग रहे हैं पर सरकार तो दे ही नहीं रही है। पटवारी ने कहा कि सरकार से यह मांग है कि इन्वेस्टर समिट का श्वेत पत्र जारी करे।

आईएएस-आईपीएस की संपत्ति का ब्योरा जुटा रहे– पटवारी ने मीडिया के सामने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले आईएएस-आईपीएस अफसरों की वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। किस आईएएस-आईपीएस की कितनी संपत्ति कहां-कहां है। इसका ब्योरा मांग रहे हैं।

एमपी के लोगों को बिजनेस टूरिज्म वीजा नहीं मिल रहा

42 देशों में जाने के लिए जरूरी वैक्सीनेशन बंद

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के सैकड़ों लोगों की विदेश यात्रा की तैयारी पर ब्रेक लग गया है। उन्हें अब एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा मिलने में परेशानी हो रही है। दरअसल, 42 देशों की यात्रा के लिए जरूरी वैक्सीनेशन एम्स भोपाल में बंद हो गया है और वीजा के लिए इसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है।

यह वैक्सीनेशन यलो फीवर के लिए होता है। अफ्रीका और लैटिसन अमेरिका के कई हिस्सों में यलो फीवर की बिमारी पाई जाती है। ऐसे में यहां यात्रा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। एम्स भोपाल प्रदेश का एकमात्र यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां हर महीने करीब 200 से 250 लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं।

हालांकि अब एम्स भोपाल में यलो फीवर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते वैक्सीनेशन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और अगली खेप कब आएगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

वैक्सीन सप्लाई में आई रुकावट– डॉक्टरों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने यलो फीवर वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वैक्सीन ब्राजील, फ्रांस और रूस में बनती है और वहां से विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए भारत सरकार को दी जाती है।

इसके बाद वैक्सीन की खेप हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) भेजी जाती है, जहां गुणवत्ता जांच के बाद देशभर के सेंटरों में आपूर्ति की जाती है।

देश में 63 सेंटर, मध्यप्रदेश में सिर्फ एक– भारत में यलो फीवर टीकाकरण के लिए कुल 63 अधिकृत केंद्र हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एम्स भोपाल ही यह सुविधा देता है। अब जब यहां वैक्सीन खत्म हो गई है, तो यात्रियों को देश के अन्य राज्यों के सेंटरों का रुख करना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे।

एम्स भोपाल ने कहा– नई खेप आने पर सूचना देंगे

एम्स भोपाल के यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. सूर्य बाली के मुताबिक, हमारे पास वर्तमान में वैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं है। हर बुधवार को लगने वाले टीकाकरण सत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। जब नई खेप आएगी, तभी टीकाकरण दोबारा शुरू किया जा सकेगा।

एम्स ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पब्लिक नोटिस जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के लिए यहां न आएं और देश के किसी अन्य अधिकृत सेंटर में ऑप्शनल व्यवस्था करें। नई खेप आने पर इसकी सूचना अलग से दी जाएगी।

उज्जैन में पंचायत ने पुजारी के बहिष्कार का फैसला बदला

विवाद बढ़ता देखकर कहा– गलती हो गई, पुजारी बोले– अब फैसला कोर्ट ही करेगा

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के पीरझलार गांव से एक पुजारी परिवार का गांव के लोगों की पंचायत ने बहिष्कार कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला बढ़ता देख गांव वालों ने बहिष्कार का फैसला यह कहते हुए वापस ले लिया कि गलती हो गई। वहीं, पुजारी का कहना है कि फैसला अब कोर्ट ही करेगा। मंदिर में 14 जुलाई को बुलाई गई पंचायत में एक युवक ने पुजारी परिवार के बहिष्कार का फैसला माइक पर पढ़कर सुनाया। इस पर गांव वालों ने हाथ उठाकर सहमति जताई थी।

सोशल मीडिया पर बढ़ा–चढ़ाकर बताया मामला– गांव में स्कूल के पास एक चाय की दुकान पर कुछ लोग चर्चा में मशगूल थे। पुजारी के मामले में पूछने पर बोले कि ऐसा कोई भारी विवाद नहीं है। मंदिर को लेकर एक छोटी सी बातचीत हुई और बतंगड़ बन गया। सोशल मीडिया पर देखा तब हमें पता चला कि यह तो हमारे गांव का मामला है और इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है।

प्रदेश में सांपों ने 4000 से ज्यादा लोगों को कांटा

सबसे ज्यादा सागर के पीड़ित, प्रदेश में हर साल ढाई हजार से ज्यादा मौतें

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में इस साल सांपों ने 4000 से ज्यादा लोगों को कांटा है, हालांकि ये आकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। साल 2024 और 2025 के जून महीने के आंकडे बताते हैं कि इस बार 728 कम लोग सर्पदंश का शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित सागर के है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सांप के काटने से मध्यप्रदेश में हर साल ढाई हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस 108 ने गुरुवार को एमपी स्नेक बाइट केस रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार, साल 2024 में जून महीने तक 4 हजार 933 लोगों और साल 2025 में जून महीने तक 4 हजार 205 लोगों को सांप ने कांटा है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।

सबसे ज्यादा सागर में पीड़ित– आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा सर्पदंश के पीड़ित सागर में दर्ज हुए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गाय। यहां साल 2025 जून माह तक 311 लोगों को सांप ने कांटा। वहीं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस 223 रीवा जिले से सामने आए।

प्रदेश में हर साल ढाई हजार से ज्यादा मौतें– सांप के काटने से मध्यप्रदेश में हर साल ढाई हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से 2024 यानी 4 सालों में सर्पदंश के कारण करीब 10 हजार 700 लोगों की मौत हुई। हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सरकारी मुआवजा दिया गया। यानी 427 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्त-भार सरकार पर आया। इतनी लागत से एक 5 मंजिला स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू हो सकता है।

सबसे कम श्योपुर में पीड़ित

एमपी में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल जाने वाले सर्पदंश पीड़ित, सबसे कम श्योपुर से सामने आए। यहां इस साल जून माह तक सिर्फ 18 केस दर्ज हुए। इसके बाद 19 केस शुजालपुर और 23 केस उज्जैन में दर्ज हुए।

भोपाल में 68 लोगों को कांटा सांप ने

इस साल भोपाल में 68 लोगों को सांप ने कांटा है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 8 लोगों की इस सीजन में सर्पदंश के कारण भोपाल में मौत भी हुई है।

हालांकि, यह आंकड़े सिर्फ उन मरीजों के हैं जो एम्बुलेंस 108 से अस्पताल पहुंचाए गए। इसके अलावा निजी वाहन व अन्य तरीके से अस्पताल पहुंचने वाले पीड़ितों के आंकड़े भी इसमें जोड़े जाएं, तो यह कई गुना तक बढ़ जाएंगे।